सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh
Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 108, नई दिल्ली, मंगलवार, 14 फरवरी 2023, पेज 8

NEWS TRANSPORT VISHESH NTV
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 पृथला हाइवे पर दौड़ेंगे वाहन
05 दिव्यांगजनों के लिए गाड़ी पंजीकरण होगा आसान
08 PM मोदी ने लड़ाकू विमानों की जानकारी ली

आज का सुविचार

जिस व्यक्ति का मन का भाव सच्चा होता है, उस व्यक्ति का हर काम अच्छा होता है।

इनसाइड

सोनौली-दिल्ली के बीच एसी स्लीपर बस सेवा शुरू, हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना

गोरखपुर। 30 सीटर स्लीपर एसी बस में सौनौली से दिल्ली तक सफर करने के लिए यात्रियों को 2,784 रुपये किराया देना होगा। गोरखपुर से दिल्ली का किराया 2485 रुपये तय किया गया है, जबकि लखनऊ तक जाने वाले यात्रियों को 932 रुपये देने होंगे। पहली बार सौनौली-दिल्ली वाया गोरखपुर की बीच परिवहन निगम ने दो एसी स्लीपर बस सेवा की शुरूआत की है। रविवार की शाम एसपी यातायात डॉ. एमपी सिंह और आरएम रोडवेज पीके तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। 30 सीटर स्लीपर एसी बस में सौनौली से दिल्ली तक सफर करने के लिए यात्रियों को 2,784 रुपये किराया देना होगा। गोरखपुर से दिल्ली का किराया 2485 रुपये तय किया गया है, जबकि लखनऊ तक जाने वाले यात्रियों को 932 रुपये देने होंगे। सौनौली से रोजाना शाम 5:30 बजे चलकर यह बस अगले दिन सुबह आठ बजे दिल्ली पहुंचेगी। गोरखपुर से इस सेवा के छूटने का समय रात के 8:30 बजे तय है। दिल्ली से चलने वाली दूसरी बस शाम 5:30 बजे छूटकर अगले दिन सुबह पांच बजे गोरखपुर पहुंचेगी। बस से यात्रा करने के लिए ऑनलाइन टिकट की सुविधा के साथ ही यदि सीट खाली है तो बस में भी टिकट दिए जाने की सुविधा मिलेगी। बस सेवा के शुभारंभ अवसर पर एआरएम गोरखपुर डिपो महेश चंद्र, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी मनोज मणि व सुधीर श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

दिव्यांगों को सरकार का बड़ा तोहफा
गाड़ी को कस्टमाइज कराना होगा और भी आसान

- MoRTH ने पूर्ण निर्मित वाहनों को Adapted vehicle में बदलने पर नोटिफिकेशन जारी किया है.

संजय बाटला

नई दिल्ली। भारत सरकार दिव्यांगजनों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करती है. इसी क्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने दिव्यांगों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने दिव्यांगों को अस्थायी रजिस्ट्रेशन के जरिए गाड़ी को कस्टमाइज कराने की सुविधा दी है. MoRTH ने पूर्ण निर्मित वाहनों को Adapted vehicle में बदलने पर नोटिफिकेशन जारी किया है.

दिव्यांगों की खास जरूरतों के अनुसार, अक्सर उनकी मोबिलिटी को सुविधाजनक बनाने के लिए Adapted vehicle की जरूरत होती है. वर्तमान में, इस तरह की अडेपटेशन या तो वाहनों के रजिस्ट्रेशन से पहले मैन्युफैक्चरर या उसके अधिकृत डीलर द्वारा या रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी से मंजूरी मिलने के आधार पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन के बाद किए जा सकते हैं.

क्या Adapted vehicle ?

Adapted vehicle का मतलब है एक मोटर व्हीकल जिसमें किसी दिव्यांगजन के उपयोग के लिए सेक्शन 52 के सब-सेक्शन (2) के तहत बदलाव किए गए हैं. इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों के अपेडटेशन के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नियम 53A और 53B में संशोधन का प्रस्ताव किया है.

संशोधन नियमों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-

नियम 53A में अस्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के आधार का विस्तार किया गया है, जिसमें पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहनों के मामलों को शामिल किया गया है जिन्हें Adapted vehicle में बदला जाना है. नियम 53B में सब-नियम2 के तहत एक प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है. इसमें कहा गया है कि पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन को Adapted vehicle में बदलने के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन की वैधता 45 दिन होगी, साथ ही अगर मोटरवाहन उस राज्य के अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड किया जा रहा है जिसमें डीलर है.

इन संशोधनों से दिव्यांगों द्वारा मोटरवाहन चलाने में और सुविधा होगी. सभी हितधारकों से टिप्पणी और सुझाव 30 दिन की अवधि के अंदर भेजे जा सकते हैं.

देश में लगातार बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन, नितिन गडकरी का दावा 2030 तक होंगे दो करोड़

एनटीवी संवाददाता

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि हर साल देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और साल 2030 तक इनकी संख्या दो करोड़ हो सकती है।

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि साल 2030 तक देशभर में दो करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन हो सकते हैं। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि देशभर में अभी कितने इलेक्ट्रिक वाहन हैं और कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या देशभर में बढ़ रही है।

होंगे दो करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि देशभर में काफी तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि आज देशभर में 20.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं। 2021 की तुलना में 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन है और इनमें 300 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। 2030 तक मेरे अनुमान के मुताबिक दो करोड़ वाहन हो जाएंगे।

यूपी में हैं सबसे ज्यादा ईवी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक 4.5 लाख दो पहिया वाहन हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी जिससे 10 लाख रोजगार भी पैदा होंगे।

पांच साल में दोगुना करने का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मौजूदा समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.8 लाख करोड़ रुपये की है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने चार करोड़ रोजगार दिए हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा जीएसटी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही मिलता है। मेरा लक्ष्य है कि इस 7.8 लाख करोड़ रुपये की इंडस्ट्री को पांच साल में 15 लाख करोड़ रुपये की इंडस्ट्री बनाना है।

जनसंख्या से ज्यादा होंगे वाहन

गडकरी ने बताया कि मौजूदा समय में देश में 30 करोड़ से ज्यादा वाहन हैं। 10 साल बाद जनसंख्या कम होगी और वाहनों की संख्या काफी ज्यादा होगी। हर घर में तीन लोग होंगे और पांच गाड़ियां होंगी, फिलहाल दिल्ली और मुंबई में ऐसा ही है। इसका मुख्य कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का लगातार बड़ा होना है।

स्क्रैपिंग से मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार 10 और 15 साल पुराने 10 लाख वाहन को स्क्रैप कर रही है। अगर भारत सरकार और राज्य सरकारों के 45 लाख वाहन स्क्रैप होंगे तो इसका क्या परिणाम होगा, आप सोच सकते हैं। ऐसा करने से ऑटो कंपोनेंट्स 30 फीसदी सस्ते हो जाएंगे। अभी हम एल्यूमीनियम इंपोर्ट करते हैं, कॉपर इंपोर्ट करते हैं। दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसे देशों से एल्यूमीनियम आता है जिसकी कीमत 145 रुपये किलो है। अगर स्क्रैप से इसकी पूर्ति होगी तो उसकी कॉस्ट 80 रुपये किलो होगी।

> केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि देशभर में काफी तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि आज देशभर में 20.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं। 2021 की तुलना में 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन है और इनमें 300 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। 2030 तक मेरे अनुमान के मुताबिक दो करोड़ वाहन हो जाएंगे।

नया पुल बनाने की योजना:सुदामडीह में धनबाद-चंदनकियारी के बीच दामोदर पर बनेगा नया 4 लेन पुल

एनटीवी संवाददाता

एनएच डिवीजन की तकनीकी टीम ने किया स्थल निरीक्षण, मार्च तक केंद्र को भेज दी जाएगी डीपीआर

नई दिल्ली। धनबाद के भौंरा में दामोदर नदी पर नया सड़क पुल बनेगा। इस निर्माण एनएच-218 पर बने 42 साल पुराने बिरसा मुंडा सेतु की बगल में करने की योजना है। साल 1980 में धनबाद के सुदामडीह इलाके को बोकारो के चंदनकियारी और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से जोड़ने के लिए पुल बनाया गया था। यह अब काफी जर्जर हो चला है। इसे देखते हुए झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के एनएच डिवीजन ने नए पुल की योजना तैयार की है। यह 4 लेन का यानी करीब 18 मीटर चौड़ा होगा।

दोनों तरफ पार पथ यानी पैदल चलने के लिए जगह होगी। निर्माण पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। पुल निर्माण के सिलसिले में एनएच डिवीजन की एक तकनीकी टीम ने शनिवार को चीफ इंजीनियर शाहिद कमर फरीदी के नेतृत्व में मौजूदा पुल के चारों तरफ जमीन की भौतिक स्थिति की जांच की।

मौजूदा पुल से पश्चिम की तरफ 25-30 की दूरी की जमीन उपयुक्त पाई गई। एनएच डिवीजन मार्च तक डीपीआर तैयार कर तकनीकी मंजूरी के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज देगा। निर्माण के लिए राशि मंत्रालय की ओर से ही उपलब्ध कराई जाएगी।

भौंरा-मानपुर के बीच रेल ओवरब्रिज भी बनेगा

एनएच डिवीजन ने सुदामडीह में ही भौंरा और मानपुर के बीच रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) बनाने की योजना भी तैयार की है। स्वायल टेस्ट भी किया जा चुका है। एनएच डिवीजन के अनुसार, आरओबी के निर्माण पर 48 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। डीपीआर पहले भी बनाई गई थी, लेकिन फिर योजना में कुछ संशोधन किया गया। एनएच डिवीजन के मुताबिक, जल्द ही रिवाइज्ड डीपीआर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज दी जाएगी।

दो लेन के पुल पर हेवी ट्रैफिक, लगता है जाम

एनएच धनबाद के कार्यपालक अभियंता दिलीप कुमार साहा कहते हैं कि मौजूदा पुल दो लेन का है और जर्जर हो चला है। धनबाद-चंदनकियारी के बीच चलनेवाली वाहनों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। पुल पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। इसे देखते हुए नए पुल की जरूरत महसूस की गई।

लाइफ स्पैन पूरा होने के करीब, विकल्प जरूरी

विभाग के मुताबिक, ज्यादापुर पुलों का लाइफ स्पैन 40-45 साल का होता है। मौजूदा पुल के बने भी 42 साल गुजर चुके हैं। इसलिए विकल्प के तौर पर नए पुल की योजना बनाई गई। इसके बनने से धनबाद के सिंदरी, झरिया, बलियापुर, सुदामडीह से चंदनकियारी, पुरुलिया, जमशेदपुर जाने में सुविधा होगी।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

इसके लागू होने से सभी बसों में नई इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) का इस्तेमाल किया जाएगा।

बस हो या मेट्रो... नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से करें सफर, राजधानी में जल्द होगी शुरुआत

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बसों में डिजिटल टिकटिंग की सुविधा शुरू करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लागू होने से सभी बसों में नई इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) का इस्तेमाल किया जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में जल्द ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) से यात्रियों को सफर का मौका मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बसों में डिजिटल टिकटिंग की सुविधा शुरू करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लागू होने से सभी बसों में नई इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली की करीब 7400 बसों में एनसीएमसी की सुविधा शुरू करने के लिए नई ईटीएम लगाई जाएंगी। तीन महीने के अंदर एनसीएमसी कार्ड का इस्तेमाल बसों के साथ-साथ मेट्रो में भी किया जाएगा।

एनसीएमसी कार्ड के लागू होने से यात्रियों को टिकट के लिए खुले पैसे रखने की चिंता रहेगी और न ही टिकट के लिए बार बार नकद भुगतान करना होगा। कार्ड के जरिये ऑनलाइन भुगतान कर बसों में सफर की सुविधा मिलने से यात्रियों की परेशानी काफी कम हो जाएंगी। दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) की तरफ से चलाई जा रही क्लस्टर बसों में डिजिटल टिकटिंग प्रणाली को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) के लिए तैयार कर रहा है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मैन्युअल टिकटिंग प्रक्रिया को समाप्त कर, डिजिटल या संपर्क रहित टिकटिंग सुविधा मुहैया करना है। डिजिटल टिकटिंग समाधान के लिए परिवहन विभाग अलग अलग रूटों पर अध्ययन कर रहा है। जारी टेंडर में 7400 बसों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) की आपूर्ति संचालन शामिल है। इसमें नकद भुगतान के बजाय टिकट खरीदने के लिए स्मार्ट कार्ड या एनसीएमसी कार्ड का प्रावधान भी शामिल है।

ऑनलाइन टिकट बुक करने पर 10 फीसदी छूटडिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए डीटीसी की बसों के टिकट ऑनलाइन बुक करने पर 10 फीसदी की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही फिलहाल वन दिल्ली और चार्टर ए से भी बसों में सफर करने के लिए टिकट खरीदने की सुविधा है। एनसीएमसी लागू होने से यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग के लिए कई तरह के टिकट और दैनिक पास खरीदने की भी सुविधा होगी। महिलाओं को बसों में निशुल्क सफर के लिए ईटीएम से पिंक टिकट भी ईटीएम से जारी किए जा सकेंगे।

एप के साथ कर सकेंगे कार्ड का भी इस्तेमाल

दिल्ली की बसों में चार्टर एप और वन दिल्ली एप से ऑनलाइन टिकट खरीदने की सुविधा है। संभावना जताई जा रही है कि अगले दो-तीन महीने में दिल्ली की सभी बसों में एनसीएमसी कार्ड चलने लगेंगे। हालांकि, डीटीसी की बसों में फिलहाल डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं है और पुरानी बसों में एनसीएमसी की सुविधा देने के लिए जरूरी बदलाव भी करना होगा। खास बात यह होगी कि एनसीएमसी कार्ड का इस्तेमाल बसों के साथ साथ मेट्रो में भी किया जा सकेगा।

इनसाइड

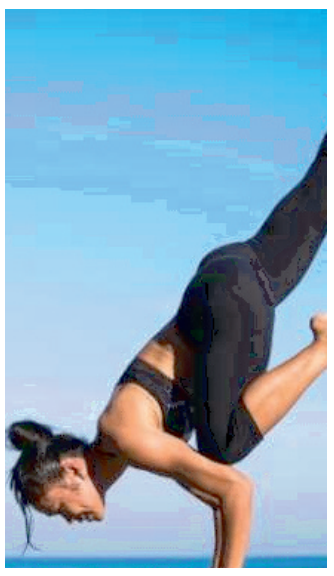

महिलाएं हर दिन करें ये 3 योगासन, बिना जिम के मिलेगा स्लिम-ट्रिम लुक

एक्सरसाइज या योग करना सेहत के लिए फायदेमंद है. नियमित योग और एक्सरसाइज करने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है. इससे कई बीमारियों से निजात भी मिलती है. बिजी रहने की वजह से या घर से बाहर न जाने की आदत के चलते कई बार महिलाओं के लिए जिम या योग केंद्र जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. कई बार महिलाएं चाहते हुए भी जिम नहीं जा पाती हैं और अपनी सेहत के साथ समझौता कर लेती हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो घर में रहकर भी कुछ खास योगासन की मदद ले सकती हैं. जो आपको स्वस्थ रखने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं.

यूपी के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट की क्लीनिकल योग इंस्ट्रक्टर डॉ. वंदना अवस्थी से उन योगासनों के बारे में जानते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने के साथ कई बीमारियों से राहत देने में मदद करेंगे. वैसे तो कोई भी आसन सुबह के समय करना बेहतर होता है लेकिन समय न मिलने पर जब भी करें तो खाना खाने के बाद कम से कम दो घंटे का गैप जरूर रखें. इतना ही नहीं इन योगासनों को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

चक्की चलनासन

इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर योगा मैट बिछाकर बैठ जायें. अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर मैक्सिमम गैप बनाएं. इस दौरान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे. अब हाथों को जमीन पर एकदम सामने की ओर सीधा रखकर उंगलियों को आपस में फंसा लें. फिर अपने हाथों को क्लॉक वाइज यानी दायीं से बायीं तरह गोल-गोल उसी तरह से घुमायें जैसे चक्की चलाई जाती है. इसके बाद विपरीत दिशा में यही प्रक्रिया दोहराएं. इस योगासन को शुरू में एक-दो मिनट करें फिर धीरे-धीरे समय को बढ़ाएं. इस योगासन से पीसीओडी की दिक्कत में राहत मिलती है. जिससे अनियमित मासिक धर्म धीरे-धीरे नियमित होने लगता है साथ ही दर्द और ऐंठन से भी राहत मिलती है. इतना ही नहीं ये मेंटल स्ट्रेस को कम करने और मोटापे से निजात दिलाने में भी मदद करता है.

तितली आसन

तितली आसन करने के लिए योगा मैट पर सूर्य की ओर मुख कर के आराम की मुद्रा में बैठें. फिर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला कर इस तरह से मोड़ें जिससे दोनों पैरों के तलवे आपस में मिल जायें. अब दोनों हाथों से पैर के तलवों को अच्छी तरह से पकड़ लें.अब तितली की तरह अपने पैरों को हिलाएं. इस आसन को भी शुरू में एक-दो मिनट करें फिर अपनी कैपिसिटी के अनुसार धीरे-धीरे इसका समय बढ़ाएं. तितली आसन करने से भी पीसीओडी की दिक्कत से राहत मिलती है. साथ ही पीठ का दर्द और मसल्स स्ट्रेस भी दूर होता है. इतना ही नहीं इस आसन को तीन महीने की गर्भावस्था के बाद भी किया जा सकता है. ये आसन डिलीवरी को आसान बनाने में भी मदद करता है. नियमित रूप से तितली आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है.

दंडासन

दंडासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठ जायें और पैरों को सामने की ओर फैला कर आपस में मिला लें. फिर दोनों हाथों को कंधों के बराबर अपनी जांघों के पास सीधा जमीन पर रखें.इस बीच रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें. अब दोनों पैरों के पंजो को अपनी ओर खींचें, कुछ सेकेंड रोक कर रखें फिर ढीला छोड़ दें. इस प्रक्रिया को दस से पंद्रह बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दोहराएं.

इ

स आसन को किसी भी आयु और अवस्था की महिलाएं आसानी से कर सकती हैं. दंडासन करने से कंधों में खिंचाव की दिक्कत कम होती है. रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है, मांसपेशियों को

महिलाएं 'घर का काम' करना बंद कर दें तो क्या होगा?

अनंत प्रकाश

चीन की एक अदालत ने हाल ही में तलाक़ से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फ़ैसला दिया है. कोर्ट ने एक व्यक्ति को निर्देश दिया है कि वह पाँच साल तक चली शादी के दौरान पत्नी द्वारा किए गए घरेलू काम के बदले में उसे मुआवजा दे. इस मामले में महिला को 5.65 लाख रुपये दिए जाएंगे.

लेकिन इस फ़ैसले ने चीन समेत दुनिया भर में बड़ी बहस को जन्म दिया है. चीनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस मामले में लोगों की राय बंटी हुई है.

कुछ लोगों का मानना है कि महिला घर के काम के बदले में मुआवज़े के रूप में कुछ भी लेने की हक़दार नहीं हैं. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि जब महिला अपने करियर से जुड़े अवसरों को त्याग कर हर रोज़ घंटों घरेलू काम करती हैं तो उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए.

इससे पहले जनवरी महीने में भारत की सर्वोच्च अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा था कि ₹घर का काम परिवार की आर्थिक स्थिति में वास्तविक रूप से योगदान करता है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है.₹

और ये पहला मौका नहीं था अदालतों ने 'घर के काम' को आर्थिक गतिविधि के रूप में स्वीकृति दिलाने वाले फ़ैसले दिये हों. चीन से लेकर भारत और पश्चिमी दुनिया के देशों में अदालतें बार - बार महिलाओं द्वारा किए गए अवैतनिक श्रम (अनपेड लेबर) को आर्थिक उत्पादन के रूप में स्थापित करने वाले फैसले देती रही हैं.

लेकिन इसके बावजूद 'घर के काम' को जीडीपी में योगदान के रूप में नहीं देखा जाता है. यही नहीं, समाज घर के काम को वह अहमियत नहीं देता है जितनी नौकरी या व्यवसाय में किए गए काम को देता है.

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर महिलाएं 'घर के काम' छोड़कर नौकरी या व्यवसाय शुरू कर दें तो क्या होगा.

'घर के काम' के मायने क्या हैं?

दुनिया की अधिकांश महिलाएं इस सवाल से जूझती हैं कि समाज एक गृहिणी के रूप में उनके द्वारा किए गए 'घर के काम' को वो सम्मान क्यों नहीं दिया जाता जो पुरुषों द्वारा किए गए काम को दिया जाता है.

जबकि एक गृहिणी के रूप में महिलाओं के काम के घंटे पुरुषों के किए गए काम के घंटों की तुलना में कहीं अधिक होते हैं.

सालों तक पत्रकारिता के साथ-साथ घरेलू काम से जुड़ी ज़िम्मेदारियां उठाने वाली कृतिका खुद इस सवाल से जूझ रही हैं.

वे कहती हैं, ₹मुझे कभी समझ नहीं आया कि लोग घर के काम को अहमियत क्यों नहीं देते? ऐसे माना जाता है कि घर का काम मतलब कोई काम ही नहीं. जबकि घर के काम आसान नहीं होते. घर पर अगर किसी को तय समय पर दवा देनी है, तो वो काम करना है, खाना तय समय पर बनना है, तो बनना है. इसमें किसी तरह की राहत नहीं मिलती.

इन सबके बाद अगर किसी को शाम को भूख लग गई तो उसके लिए भी कुछ न कुछ बनाना होता है. सही कहूं तो घर के काम करने वाली महिला को 'अलादीन का चिराग़' समझा जाता है. मेरे पास इससे सटीक मेटाफ़र नहीं है. अगर कभी सहयोग की माँग की भी जाए तो कहा जाता है कि करती ही क्या हो... मम्मी भी करती थीं उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा.

महिला, अवैतनिक श्रम

आँकड़ों को देखें तो पता चलता है कि भारत में घर के काम में महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं.

ताजा टाइम यूज़ सर्वे के मुताबिक़, महिलाएं हर दिन घर के काम (अवैतनिक घरेलू कार्य) में 299 मिनट लगाती हैं. वहीं, भारतीय पुरुष दिन में सिर्फ 97 मिनट घर के काम में लगाते हैं.

यही नहीं, इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि महिलाएं घर के सदस्यों का ख़याल रखने में रोज़ 134 मिनट लगाती हैं. वहीं, पुरुष इस काम में सिर्फ 76 मिनट ख़र्च करते हैं.

आर्थिक मूल्य निकालना मुश्किल है?

ध्यान से देखें तो हर काम का कोई न कोई मूल्य होता है. तो ये कैसे संभव है कि महिलाओं द्वारा घर पर रहकर किए गए काम की कोई आर्थिक मूल्य न हो?

किसी भी काम का मूल्य निकालने के लिए ज़रूरी है कि उस काम का ठीक-ठीक आकलन किया जाए. महिलाओं के किए गए अवैतनिक घरेलू श्रम यानी 'घर के काम' का मूल्य निकालने के लिए तीन फॉर्मूले उपलब्ध हैं -

अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड इनपुट/आउटपुट कॉस्ट मेथड

पहले फ़ॉर्मूले के मुताबिक़, अगर कोई महिला बाहर जाकर पचास हज़ार रुपये कमा सकती है और इसके बावजूद वह घर के काम करती है तो उसके काम की कीमत पचास हज़ार रुपये मानी जानी चाहिए.

वहीं, दूसरे फ़ॉर्मूले के मुताबिक़, एक महिला द्वारा किए गए 'घर के काम' का मूल्य उन सेवाओं के लिए किए किए जाने वाले खर्च के आधार पर तय होती है. सरल शब्दों में कहें तो अगर एक महिला की जगह घर पर कोई और काम करता है तो जो ख़र्च उसकी सेवाएं लेने के बदले में होगा, वही उस महिला के द्वारा किए गए काम का मूल्य होगा.

इसी तरह तीसरे फॉर्मूले में एक महिला द्वारा घर पर किए गए काम की मार्केट वेल्यू निकाली जाती है.

लेकिन इनमें से कोई भी फॉर्मूला भावनात्मक रूप से दी गई सेवाओं का सही मूल्य नहीं निकालता है.

अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान

अंतरराष्ट्रीय संस्था ऑक्सफेम के एक अध्ययन के मुताबिक़, महिलाओं द्वारा किए गए 'घर के काम' का मूल्य भारतीय अर्थव्यवस्था का 3.1 फीसदी है.

साल 2019 में महिलाओं द्वारा किए गए 'घर के काम' की क़ामत दस ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा थी. ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट की पचास सबसे बड़ी कंपनियों जैसे वॉलमार्ट, ऐप्पल और अमेज़न आदि की कुल आमदनी से भी ज़्यादा थी.

इसके बाद भी भारतीय अदालतों को बार-बार गृहणियों के काम को आर्थिक मायने देने के लिए फ़ैसले देने पड़ते हैं.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा है, ₹एक गृहिणी की आमदनी को निर्धारित करने का मुद्दा काफ़ी अहम है. यह उन तमाम महिलाओं के काम को मान्यता देता है, जो चाहे विकल्प के रूप में या सामाजिक/सांस्कृतिक मानदंडों के परिणामस्वरूप इस गतिविधि में लगी हुई हैं.

यह बड़े पैमाने पर समाज को संकेत देता कि क़ानून और न्यायालय गृहणियों की मेहनत, सेवाओं और बलिदानों के मूल्य में विश्वास करता है.₹

यह इस विचार की स्वीकृति है कि ये गतिविधियां परिवार की आर्थिक स्थिति में वास्तविक रूप से योगदान करती हैं और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं. इस तथ्य के बावजूद इन्हें पारंपरिक रूप से आर्थिक विश्लेषण से बाहर रखा गया है. यह बदलते दृष्टिकोण, मानसिकता और हमारे अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्वों का प्रतीक है. और, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सामाजिक समानता की संवैधानिक दृष्टि की ओर एक कदम है और सभी व्यक्तियों को जीवन की गरिमा सुनिश्चित करता है.₹

कामकाजी महिलाओं की बेटियों का करियर बेहतर?

महिलाएं जो काम करती हैं वो क्या है?

ध्यान से देखें तो गृहणी के रूप में काम के दौरान महिलाएं तीन वर्गों को अपनी सेवाएं देती हैं. पहला वर्ग वरिष्ठ नागरिक जो देश की आर्थिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे चुके होते हैं, दूसरा युवा वर्ग जो वर्तमान में जीडीपी में योगदान दे रहे हैं और तीसरा बच्चे जो आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे.

तकनीकी भाषा में इसे अब्सट्रेक्ट लेबर कहा जाता है. ये एक ऐसा श्रम है कि जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से लगे श्रम के पुनर्जीवन में सीधे-सीधे अपना योगदान देता है.

भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुशीला चानू अपने घर में चाय बनाते हुए

सरल शब्दों में कहें तो एक महिला अपने पति के कपड़े धोने, प्रेस करने से लेकर उसके खाने-पीने, शारीरिक एवं मानसिक सेहत आदि का ख़याल रखती है ताकि ऑफ़िस जाकर काम कर सके. वह बच्चों को पढ़ाती है ताकि वो बाद में देश के मानव संसाधन का हिस्सा बन सकें. वह अपने माता-पिता और सास-ससुर की सेहत का ध्यान रखती हैं जो देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे चुके होते हैं.

अब अगर इस पूरे समीकरण में से गृहणी को निकाल दिया जाए तो सरकार को बच्चों का ध्यान रखने के लिए बाल कल्याण सेवाओं, वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखने के वृद्धाश्रम, केयर गिवर आदि पर बेतहाशा खर्च करना पड़ेगा.

क्या होगा अगर महिलाएं काम बंद कर दें?

फिलहाल, ये काम ग्रहणियां कर रही हैं जो मूलतः सरकार के हिस्से का काम है क्योंकि एक नागरिक की देखभाल की ज़िम्मेदारी राष्ट्र की होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर महिलाएं फ्री में सरकार के लिए काम करना बंद कर दें तो क्या होगा?

असंगठित क्षेत्र एवं श्रम से जुड़े विषयों पर अध्ययन कर चुकीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर अर्चना प्रसाद मानती हैं कि यदि महिलाएं घर के काम ही बंद कर दें तो ये सिस्टम पूरी तरह ठप हो जाएगा.

वे कहती हैं, महिलाएं ये अनपेड काम करना बंद कर दें तो पूरा तंत्र ही ठप हो जाएगा. क्योंकि महिला का अनपेड वर्क ही तो सिस्टम को सब्सिडाइज़ करता है. अगर घर के काम और केयर से जुड़े काम का ख़र्च सरकार या कंपनियों को वहन करना होगा तो श्रम की मूल्य काफ़ी बढ़ जाएगा.

क्योंकि महिलाएं श्रम शक्ति को पुनर्जीवित कर रही हैं. उसे संभाल रही हैं. इस तरह से हर आदमी के श्रम में महिला का अनपेड श्रम शामिल है. तकनीकी भाषा में हम इसे अब्सट्रेक्ट लेबर कहते हैं.

महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू काम को जीडीपी में योगदान के रूप में स्वीकार्यता दिलाने की पक्षधर अर्थशास्त्री, लेखिका और न्यूजीलैंड की राजनेता मर्लिन वैरिंग मानती हैं कि जीडीपी में महिला द्वारा गर्भधारण तक को एक उत्पादक गतिविधि नहीं माना जाता है जबकि वह भविष्य के मानव संसाधन को जन्म देती हैं.

अपने देश का उदाहरण देते हुए वे कहती हैं, ₹न्यूजीलैंड के नेशनल अकाउंट्स, जहां से जीडीपी के आँकड़े मिलते हैं, में गाय, बकरी, भेड़ और भैंस के दूध की कीमत है लेकिन माँ के दूध की कोई कीमत नहीं है जबकि वह दुनिया का सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ है. ये बच्चे की सेहत और शिक्षा में सबसे अच्छा निवेश है लेकिन इसे गिना नहीं जाता है.₹

आर्थिक पहचान कैसे दी जाए?

अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर के काम को किस तरह आर्थिक पहचान दी जा सकती है.

अवैतनिक श्रम पर कई किताबें लिख चुकीं अहमदाबाद स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स में अर्थशास्त्र की प्रोफ़ेसर इंदिरा हीरवे मानती हैं कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम को एक उत्पादन की तरह देखा जाना चाहिए.

वे कहती हैं, ₹घर में महिलाएं जो खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बाज़ार से सामान लाती हैं, बच्चों की केयर करती हैं, घर में बीमार लोगों का ख़याल रखती हैं - वो सर्विस है यानी सीधे-सीधे उत्पादन से जुड़ा है. ये काम देश की आमदनी और देश को सेहतमंद रखने में उनका योगदान है.₹

अगर एक नर्स की सेवाएं ली जाएं तो उसे राष्ट्रीय आय में गिना जाता है. लेकिन यही काम अगर एक गृहिणी करे तो उसे राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है. ये ग़लत बात है. जबकि काम तो वही है. इसका कोई कारण ही नहीं है कि इन्हें राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाए. यही नहीं, वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती हैं. सरकारी क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र तकल कोई भी महिलाओं के लिए इस अवैतनिक श्रम के बिना नहीं चल सकते.₹

इतिहास के पन्ने पलटें तो एक समय ऐसा आया है जब वो हुआ है जिसके संकेत प्रोफ़ेसर हीरवे ने दिए हैं.

साल 1975 में आइसलैंड की नब्बे फीसदी महिलाओं ने 24 अक्तूबर को एक दिन के लिए खाना बनाने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल करने से इनकार कर दिया. महिलाओं के इस ऐलान का असर ये हुआ कि पूरा देश एकाएक रुक गया. काम पर गए पुरुषों को तत्काल घर वापसी करनी पड़ी और बच्चों को रेस्त्रां लेकर भागना पड़ा और वे सभी काम रुक गए जो कि आमतौर पर पुरुष किया करते थे.

लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वर्तमान समय में भी महिलाएं इस तरह का अवैतनिक श्रम करना बंद कर दें तो वही होगा जो 1975 में हुआ था.

'ख़त्म हो जाएंगे परिवार'

प्रोफ़ेसर हीरवे मानती हैं कि अगर महिलाएं घर पर काम करना बंद कर दें तो परिवार नाम की संस्था ही ख़त्म हो जाएगी.

वे कहती हैं, ₹विकास के मायने ये होते हैं कि सभी लोग अपने मन का काम कर सकें. जो महिला डॉक्टर बनना चाहे वह डॉक्टर बन सके, जो महिला इंजीनियर बनना चाहे वह इंजीनियर बन सके.₹

₹लेकिन पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं पर घर के काम थोप दिए हैं. इससे उनके पैरों में एक तरह की बेड़ियां पड़ गई हैं. उन पर ये दबाव है कि वे पहले घर के काम करें फिर कोई अन्य काम करें. अगर वे काम करना बंद कर दें तो सबसे पहले परिवार नामक संस्था ख़त्म हो जाएगी. यही नहीं, निजी क्षेत्र से लेकर सरकारी क्षेत्र आदि का काम ख़त्म हो जाएगा. आपको ये मानना होगा कि अवैतनिक श्रम के बिना अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती.₹

इंदिरा नूई का उदाहरण देते हुए हीवरे कहती हैं कि औपचारिक व्यवसायिक तंत्र में महिलाओं के बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद घर संभालने की ज़िम्मेदारी उन्हीं की होती है. वे कहती हैं, ₹एक बार इंदिरा नूई ने बताया था कि तमाम सुख-सुविधाओं के बावजूद घर चलाने की ज़िम्मेदारी उन्हीं की है. उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था. कंपनी में एक बार उन्हें प्रमोशन मिला. वे घर पहुंचीं तो दरवाज़े पर उन्हें माँ मिली जिन्होंने कहा कि जाओ जाकर दूध ले आओ, तुम्हारे पति और बच्चों को सुबह दूध की ज़रूरत होगी. इंदिरा पहले दूध लेने गईं. तो मतलब ये है कि ज़िम्मेदारी तो महिलाएं की ही होती है. ये बात कई महिला सीईओ ने भी कही है कि वे चाहे कितना तरक्की कर लें उन्हें इन कामों से छुटकारा नहीं मिल सकता है क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है.₹

इंदिरा हीरवे मानती हैं कि भारत को अपनी जीडीपी में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक श्रम को शामिल करना चाहिए.

वे कहती हैं, ₹भारतीय मौद्रिक जीडीपी की दूसरे देशों से तुलना करना ग़लत है क्योंकि भारत में महिलाएं अवैतनिक श्रम करके राष्ट्रीय आय में जो योगदान दे रही हैं उसे जीडीपी में गिना ही नहीं जाता. जबकि विदेशों में यही काम फोस्टर केयर, ओल्ड एज होम, नर्स, नैनी आदि रूपों में राष्ट्रीय आय में शामिल होता है.₹

क्या है समाधान?

दुनिया भर में कई महिलाएं और पुरुष इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था से लेकर समाज में पितृसत्ता का असर कम होना चाहिए.

जागो री मूवमेंट को चलाने वालीं कमला भसीन मानती हैं कि पहली लड़ाई तो यही है कि हम पितृसत्तात्मक समाज से बाहर निकलें.

वे कहती हैं, ₹आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि पुरुषों को ये अधिकार क्यों नहीं है कि वे अपनी बड़ी होती बेटी या बेटे के साथ जी भर के समय गुज़ार सकें. उन्हें पढ़ा लिखा सकें, उनके साथ खेल सकें.₹

पुरुष जो करते हैं वह जीविकोपार्जन का जुगाड़ है. ये जीवन नहीं है. आपकी पत्नी जो जी रही हैं, वह जीवन है. आप कुछ समय नौकरी न करें तो आपके बच्चों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. आपकी पत्नी एक दिन काम न करें तो जीवन और मृत्यु का सवाल खड़ा हो जाता है.

सोचकर देखिए कि आज अगर महिलाएं कह दें कि या तो हमारे साथ सही से व्यवहार करें नहीं तो हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे. क्या होगा? होगा ये कि सेनाएं ठप हो जाएंगी. मानव संसाधन कहां से लाएंगे आप?

लेकिन सवाल उठता है कि कहीं घर के काम को आर्थिक गतिविधि का दर्जा दिलाने की लड़ाई बहुत लंबी तो नहीं है.

पेड़-पौधों पर शोध करने वालीं रुचिता दीक्षित मानती हैं कि जहां से ग़लती शुरू हुई है, सुधार भी वहीं से शुरू होगा.

वे कहती हैं, ₹मैं एक वैज्ञानिक हूं. लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो मेरे सामने ये सवाल था कि अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार या नैनी के हवाले छोड़ दूं या नौकरी छोड़कर उसके पालन-पोषण में अपना योगदान दूं. मैंने दूसरा विकल्प चुना. लेकिन मैंने ये विकल्प चुनते हुए लोगों को ये अहसास कराया है कि ये कोई आसान काम नहीं है.₹

₹सुधार हम से ही होगा. मुझे लगता है कि हमें आने वाले कल में अपनी बेटी-बहुओं द्वारा किए गए घर के काम को वही तवज्जो देनी चाहिए जो हम लड़कों द्वारा किए गए काम को देते हैं. संतुलन तभी आएगा जब हम ये स्वीकार करेंगे कि रेडी टू ईट फूड अल्पकालिक समाधान हो सकता है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज़ घर से बाहर जाकर काम कर सकें तो आपके लिए घर पर अच्छा खाना बनना ज़रूरी है. और खाना बनाना उतना ही ज़रूरी काम है जितना ज़रूरी बाहर जाकर काम करना है.

क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए प्रोटीन? जानें डाइट में शामिल करने से क्या-क्या होते हैं फायदे

प्रोटीन के सेवन से आपको देर तक पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करती हैं. ऐसे में यह उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है

प्रोटीन के सेवन से देर तक पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करती हैं.प्रोटीन के सेवन से देर तक पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करती हैं.

प्रोटीन पुरुषों के साथ ही महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी होता है. इससे हेल्दी और फिट बॉडी लंबी उम्र तक बनाए रखने में मदद मिलती है. साथ ही, प्रोटीन मांसपेशियों के विकास और मसल्स फाइबर की मरम्मत के लिए भी जरूरी होता है. प्रोटीन एक प्रकार का मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जो मसल मास और फिजिक को बनाए रखता है. महिलाओं के लिए प्रोटीन का सेवन बहुत महत्वपूर्ण होता है. प्रोटीन की जरूरत उम्र, एक्सरसाइज लेवल, कैलोरी इनटेक और अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है. चूंकि, शरीर सभी आवश्यक अमीनो एसिड का निर्माण नहीं करता है, इसलिए सप्लीमेंट या डाइट में प्रोटीन को जरूर शामिल करना चाहिए. प्रोटीन, वसा और कार्ब्स के विपरीत, स्टोर नहीं किया जा सकता है. ऐसे में हर दिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है.

महिलाओं के लिए प्रोटीन के फायदे

हेल्थकार्ट डॉट कॉम में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रोटीन बालों, त्वचा और नाखूनों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी होता है. ये सभी केराटिन से बने होते हैं, जो एक तरह का संरचनात्मक प्रोटीन है. चूंकि, केराटिन प्रोटीन से बना होता है, इसलिए शरीर में इसका निर्माण जारी रखने के लिए प्रोटीन युक्त फूड्स का सेवन करना जरूरी है. कोलेजन भी एक प्रोटीन है, जो हमारी त्वचा के वजन का 70% हिस्सा होता है. यह शरीर का सबसे प्रमुख प्रोटीन है, जो कनेक्टिव टिशूज में पाया जाता है. यह जोड़ों को स्थिर और गतिशील बनाए रखने में मदद करता है. प्रोटीन की कमी होने से समय से पहले त्वचा पर झुर्रियां पड़ सकती हैं.

मांसपेशियों को रखे मजबूत

महिलाओं के लिए प्रोटीन मांसपेशियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है, क्योंकि यह अमीनो एसिड में उच्च होता है और मांसपेशियों में ऐंठन को दूर करता है. इससे लीन मसल मास बनाए रखने में मदद मिलती है. महिलाओं को उम्र बढ़ने के साथ ऑस्टियोपोरोसिस, अन्य हड्डियों की समस्या होने का रिस्क अधिक रहता है, ऐसे में उन्हें डायटरी प्रोटीन का सेवन अधिक करना चाहिए, ताकि मसल मास में इजाफा हो.

वजन होता है कम

प्रोटीन के सेवन से आपको देर तक पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करती हैं. ऐसे में यह उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जो वजन कम करना चाहती हैं. जिनका वजन बहुत अधिक है, वे यदि प्रोटीन ड्रिंक्स लेती हैं, तो इससे बॉडी वेट, फैट मास और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में सुधार होता है.

हड्डियां रहती हैं स्वस्थ

महिलाओं को हड्डियों से संबंधित समस्याएं बहुत होती हैं, ऐसे में सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी लेने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के लिए प्रोटीन की भी जरूरत होती है. जब आप कम मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम का सेवन करती हैं, तो प्रोटीन ही हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. अध्ययनों के अनुसार, उच्च प्रोटीन आहार लेने से बोन मिनरल डेंसिटी का लेवल अधिक और हड्डियों के नुकसान की दर कम होती है.

इनसाइड

जेलों में बड़े गैंगस्टर और सिफारिशी ही चला रहे मोबाइल, तिहाड़ प्रशासन ने 40 दिन में बरामद किए 348 फोन

नई दिल्ली। तिहाड़ प्रशासन ने दिल्ली की तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल में चेकिंग कराई। इस दौरान 40 दिन में 348 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तिहाड़ प्रशासन के एक अधिकारी ने दावा किया है कि ज्यादातर मोबाइल फोन जेलों में बंद गैंगस्टर व सिफारिशी कैदियों के कब्जे से मिले हैं।

दिल्ली की जेलों में बंद नामी गैंगस्टर जेलों में खूब मोबाइल चला रहे है और जेल से ही अपने गिरोह को चलाने के अलावा रंगदारी भी वसूल कर रहे थे। ये खुलासा उस समय हुआ है जब तिहाड़ प्रशासन ने तिहाड़, मंडोली व रोहिणी जेल में चेकिंग कराई। इस दौरान 40 दिन में 348 मोबाइल फोन बरामद किए गए।

तिहाड़ प्रशासन के एक अधिकारी ने दावा किया है कि ज्यादातर मोबाइल फोन जेलों में बंद गैंगस्टर व सिफारिशी कैदियों के कब्जे से मिले हैं। तिहाड़ प्रशासन ने इन मोबाइल फोन को जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व देश के खुफिया विभाग को सौंप दिया है।

स्पेशल सेल ने इन मोबाइल पर जांच शुरू कर दी है। ये पता किया जा रहा है कि गैंगस्टर कहां-कहां फोन कर रहे थे और किस-किस कारोबारी से रंगदारी मांगी गई है। एक अधिकारी ने तो ये भी दावा किया कि तिहाड़ से देश से बाहर भी कॉल की जा रही थीं।

स्पेशल सेल के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में गुप्त रूप से जांच की जाती है। देश से जुड़े मुद्दे को लेकर खुफिया विभाग जांच करती है। तिहाड़ के नए जेल महानिदेशक संजय बेनीवाल के पदभार संभालते ही तिहाड़ में मोबाइल चला रहे कैदियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है।

कैदियों से 348 मोबाइल फोन के अलावा बड़ी संख्या में हीटर भी मिले हैं। अधिकारी ने बताया कि ये बरामद मोबाइल बहुत पहले ही तीनों जेलों के अंदर चले गए थे। गैंगस्टर बेहिचक मोबाइल चला रहे थे। अब टीम ने वहां के कैदियों को दूसरे कैदियों को भय दूर किया है। अब कैदी खुद ही बता रहे हैं कि कौन सा बदमाश मोबाइल चला रहा है।

रंगदारी के लिए चलाते हैं मोबाइल

जेलों में सबसे ज्यादा मोबाइल गैंगस्टर व गिरोह सरगना चलाते हैं। इनको जहां गिरोह को चलाने के लिए कारोबारियों व व्यवसायियों से रंगदारी मांगनी होती है, वहीं गिरोह भी चलाना होता है। जेलों में सबसे ज्यादा फोन इस उद्देश्य से चलाए जा रहे थे। इसके अलावा परिवारवालों का हालचाल जानने, गर्लफ्रेंड के संपर्क में रहने के लिए भी मोबाइलों का इस्तेमाल हो रहा है।

मोबाइल मिलने पर यह मिलती है सजा

एक अधिकारी ने बताया कि मोबाइल मिलने पर कैदियों की सुविधाएं जैसे टीवी, परिजनों से बात कराने की सुविधा, खान-पान आदि की सुविधाएं कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। ये ऐसी सुविधाएं हैं, जिनके बंद होने पर कैदी तुरंत परेशान हो जाता है। हालांकि मोबाइल मिलने पर किसी तरफ की एफआईआर नहीं होती है। इसी का कैदी फायदा उठाते हैं।

पर्थला फ्लाईओवर पर जल्द दौड़ेंगे वाहन, नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ के लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

एनटीवी संवाददाता

नोएडा के पर्थला गोलचक्कर पर बन रहे पर्थला फ्लाईओवर का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में फ्लाईओवर पर वाहन अपनी रफ्तार भरते हुए नजर आएंगे। प्राधिकरण के पहले केबल सस्पेंशन फ्लाईओवर का काम इन दिनों युद्ध स्तर पर चल रहा है।

नई दिल्ली। पर्थला फ्लाईओवर का निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है और इस फ्लाईओवर की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर के तैयार होने से करीब 2 लाख लोगों को जाम से राहत मिलेगी।

30 से 45 मिनट की होगी बचत

पर्थला फ्लाईओवर के शुरू होने जाने के बाद गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ से आने वाले लाखों लोगों को जाम से राहत मिलेगी। साथ ही लोगों का 30 से 45 मिनट की भी बचत भी होगी।

इस महीने से शुरू होगा ट्रैफिक

नोएडा प्राधिकरण पहला केबल सस्पेंशन फ्लाईओवर बना रहा है, जिसका निर्माण जल्द ही पूरा हो वाला है, जिसके बाद इस फ्लाइओवर का लोकार्पण कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पर्थला फ्लाइओवर का 85 फीसदी से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और अथॉरिटी के अधिकारी अप्रैल के महीने से इस पर ट्रैफिक शुरू करने का दावा कर रहे हैं।

इन सोसायटी के लोगों को मिलेगा फायदा

इस फ्लाईओवर के निर्माण से सेक्टर-51, 52, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 121, 122 के हजारों निवासियों को फायदा होगा। साथ ही दिल्ली से गाजियाबाद, हापुड़, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन को जाने के लिए उक्त चौराहे पर बिना किसी रेड लाइट के सीधे पहुंचा जा सकता है।

हर रोज गुजरेंगे 25 हजार से ज्यादा वाहन

बता दें कि वर्तमान में पर्थला गोल चक्कर पर सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे तक करीब 18 हजार वाहन निकलते हैं, लेकिन इन सभी वाहन सवारों को जाम के चलते ऑफिस सही समय पर पहुंचने के लिए 30 से 45 मिनट पहले घर से निकलना पड़ता है। जबकि अधिकारियों का माना है कि फ्लाईओवर तैयार होने के बाद इस रूट से हर रोज 25 से 30 हजार वाहनें निकलाने का अनुमान है।

काम के चलते डायवर्ट हो कर निकल रहे हैं वाहन

पर्थला फ्लाईओवर का काम युद्धस्तर पर चल रहा है और काम के 31 मार्च में पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन इन दिनों काम को ध्यान में रखते हुए नोएडा-ग्रेटर नोएडा की ओर से आने-जाने वाले वाहन को सेक्टर 121 और सेक्टर 71 की ओर निकाला जा रहा है।

'यह गुंडागर्दी है...' लोगों के विरोध के बाद भी चौथे दिन भी चला बुलडोजर

DDA Demolition Drive डीडीए द्वारा महारौली में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम लोगों के विरोध के बाद भी चौथे दिन जारी है। डीडीए ने शनिवार को अतिक्रमण हटाने पर अपने बयान जारी किया था।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के महरौली में डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण, DDA) का डिमोलिशन ड्राइव (विध्वंस अभियान) लगातार चौथे दिन यानी सोमवार को भी जारी है। इस दौरान स्थानीय लोग कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

चौथे दिन भी जारी है कार्रवाई

डीडीए द्वारा की जा रही चौथे दिन की कार्रवाई की तस्वीरें समाचार एजेंसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। इससे पहले रविवार सुबह पहुंचे बुलडोजर ने आम बाग, बृजवासी कॉलोनी क्षेत्र में डीडीए की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को गिराया।

विरोध के बावजूद DDA डिमोलिशन ड्राइव जारी

इसको लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही शनिवार को दिल्ली सरकार ने भी इसका विरोध करते हुए डीडीए से डिमोलिशन ड्राइव पर रोक लगाने के लिए भी बोला था।

स्थानीय लोगों ने लगाए गंभीर आरोप

डीडीए द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में स्थानिय लोगों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। स्थानीय लोगों ने डीडीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने उन्हें एक घंटे इंतजार करने के लिए कहा था, तब तक स्थगन आदेश (स्टे नोटिस) आ जाएगा। हमने स्टे नोटिस के लिए आवेदन किया था, लेकिन वह इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। यह गुंडागर्दी है।

डीडीए ने जारी किया बयान

शनिवार को अनधिकृत अतिक्रमण हटाने के दौरान एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा, ₹राजस्व विभाग द्वारा अनधिकृत और अवैध अतिक्रमण या निर्माण की सीमा की पहचान कर दिसंबर, 2021 में डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आया हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अतिक्रमण को हटाया गया है।

12 दिसंबर को लगाया था नोटिस

पुरातात्विक पार्क में एएसआई, दिल्ली सरकार के राज्य पुरातत्व विभाग और डीडीए के करीब 55 स्मारक आते हैं। पूर्व में 12 दिसंबर, 2022 को अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर एक नोटिस चिपकाया गया था और 10 दिनों के भीतर विवादित भूमि से सभी अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था।

दिल्ली पुलिस ने जुआ खिलाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 41 लोग गिरफ्तार

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली पुलिस ने एएटीएस और ज्योति नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर ज्योति नगर इलाके में छापेमारी कर जुआ खिलाने वाले एक गिरोह का पर्दापाश करते हुए 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह लोग अपने यहां बर्थडे पार्टी के बहाने जुआ खिलाते थे।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद भी अपराधिक घटनाएं कम नहीं हो रही है। पुलिस ने ज्योति नगर इलाके में की छापेमारी के दौरान बर्थडे पार्टी के नाम पर कैसीनो स्टाइल में जुआ खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस जुए घर में छापेमारी के दौरान 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के बारे में बताते हुए एक अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई एएटीएस और ज्योति नगर पुलिस स्टेशन द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर ज्योति नगर के हरमान स्थान पर छापा मारा गया, जिससे कैसिनों स्टाइल में लोगों को जुआ खिलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड हुआ। इस छापेमारी के दौरान 41 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। आगे मामले की जांच की जा रही है।

रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं ने किया प्रदर्शन, निगम के खिलाफ की जमकर नारे बाजी

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली में रेहड़ी पटरी विक्रेता ने सिविक सेंटक के पास अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए निगम कर्मचारियों में रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार जी 20 की बैठक के चलते विक्रताओं को उजाड़ रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं ने सोमवार को सिविक सेंटर पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए दिल्ली प्रशासन का जमकर विरोध किया।

रेहड़ी पटरी विक्रेताओं ने लगाए गंभीर आरोप

रेहड़ी पटरी वालों के संगठन नास्वी के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार रेहड़ी पटरी वालों को जी 20 की बैठक के नाम पर उजाड़ रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में वेडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन 20 के नाम पर रेडी पटरी वालों की दुकानों को उजाड़ा जा रहा है।

विरोध के बावजूद DDA डिमोलिशन ड्राइव जारी

सिविक सेंटर पर अपनी मांगों के लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे रेहड़ी पटरी विक्रेताओं का कहना है कि निगम के लोग रिश्वत की मांगते हैं।

गाजियाबाद और मेरठ के 17 रैपिड ट्रेन स्टेशन से भी चलेंगी 20 सीटर बसें, विभाग ने मांगे

एनटीवी न्यूज

गाजियाबाद-मेरठ रैपिड ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के सफर को सुविधा जनक बनाने के लिए यूपी परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग को साहिबाबाद गाजियाबाद व गुलधर तीन स्टेशन से 17 रूट पर 114 बसें चलाने की अनुमति मिल गई है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद रैपिड ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने अभी से तैयारी शुरू दी हैं। रैपिड ट्रेन के साहिबाबाद, गाजियाबाद व गुलधर तीन स्टेशन से 17 रूट पर 114 बसें चलाने की अनुमति मिलने के बाद अब परिवहन अधिकारी अन्य स्टेशन से भी बसों का रूट तय कराने की कवायद में जुट गए हैं।

गाजियाबाद जिले की सीमा में आने वाले चार अन्य स्टेशन दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण व मोदीनगर उत्तरी और मेरठ जिले की सीमा में आने वाले 13 स्टेशन मेरठ दक्षिण, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रहमपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, एमईएस कालोनी, दौरली, मेरठ उत्तरी, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो से बस चलाने की तैयारी है।

आरटीओ गाजियाबाद अरुण कुमार ने बताया कि मेरठ मंडलायुक्त के निर्देशानुसार दोनों जिलों के 17 रैपिड ट्रेन स्टेशन से बसें चलाने के लिए रूट तय करने को एनसीआरटीसी के अधिकारियों को पत्र भेजा है। सर्वे के बाद एनसीआरटीसी रूट और बसों की संख्या तय करेगी। इसके बाद प्रस्ताव को आगामी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में रखकर पास कराया जाएगा। बैठक में हरी झंडी मिलने पर रूट तय हो जाएंगे।

सीएनजी या यूरो-छह श्रेणी की ही बसें चलेंगी

प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर रैपिड ट्रेन के सभी रूट पर सिर्फ प्रत्येक बस की क्षमता 20 सवारी की होगी। आरटीओ गाजियाबाद ने बताया कि साहिबाबाद, गाजियाबाद व गुलधर स्टेशन से 17 रूट पर बसें चलाने के लिए अनुमति मिलने के बाद 15 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। निजी बस आपरेटर के अलावा यूपी रोडवेज भी बसों के संचालन के लिए आवेदन कर सकता है। उक्त तिथि तक जितने आवेदन प्राप्त होंगे। अगर वह सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें परमिट जारी किए जाएंगे। इन तीन स्टेशन से बसें चलने से एक लाख से ज्यादा लोगों को रोजाना राहत मिलेगी।

तीनों अस्पतालों में शुरू होगी टोकन व्यवस्था, चिकित्सा अधिकारी ने जारी किया निर्देश

गाजियाबाद में बीते दिनों सामने आई लापवाही की घटनाओं के बाद अब एमएमजी जिला महिला और संयुक्त अस्पताल में अब मरीजों को इलाज के लिए लंबी-लंबी कतारों से राहत देते हुए टोकन व्यवस्था को लागू कर दिया है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद के एमएमजी, जिला महिला और संयुक्त अस्पताल में अब मरीजों को इलाज के लिए लंबी-लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। दैनिक जागरण में प्रमुखता से प्रकाशित की गईं पड़ताल के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है। सीएमओ डा.भवतोष शंखधर ने शनिवार को इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिया है।

जिला एमएमजी अस्पताल, जिला महिला अस्पताल और संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल के सीएमएस को जारी किए गए आदेश में लिखा है कि इलाज के लिए ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों को घंटों लंबी-लंबी कतारों में लगना पड़ता है। कई बार मरीज बेहोश होकर भी गिर पड़ते हैं। यह ठीक नहीं है। मरीजों के लिए टोकन व्यवस्था लागू की जाए। इसके लिए इलेक्ट्रानिक बोर्ड लगाए जाएं। बोर्ड पर टोकन नंबर आने पर संबंधित मरीज को चिकित्सक के कक्ष में भेजा जाए। बारी आने तक मरीज कुर्सी पर बैठेंगे।

सीएमओ ने निर्देश दिए हैं कि सीएमएस को मरीजों के बैठने और पीने के पानी का इंतजाम भी करना होगा। सीएमओ ने बताया कि विधायक अपनी निधि से इलेक्ट्रानिक बोर्ड व कुर्सियों देने को सहमत हो गए है।

मरीजों की लगी लाइन, लेकिन कक्ष पर लटका ताला

प्रदेश सरकार जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में तैनात चिकित्सकों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में आए दिन ओपीडी से चिकित्सक गायब रहते हैं। मरीजों की लंबी कतार लगी रहती है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक साथ तीन से पांच चिकित्सकों को अवकाश दे दिया जाता है। शनिवार को ओपीडी में तैनात डा. आरसी गुप्ता के कक्ष पर ताला लटका देखकर मरीज वापस लौट गए। हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. एसएन सिंह के कक्ष संख्या नौ और एनेस्थेटिस्ट डा. सूर्यांशु ओझा के कक्ष संख्या-10 पर अवकाश का बोर्ड टंगा हुआ था। सर्जन डा. संजय गुप्ता का कक्ष संख्या तीन भी बंद था। केवल डा. अर्चना सिंह, डा. मदन लाल, डा. योगेंद्र और डा. राका ओपीडी में बैठकर सभी तरह के रोगियों को देख रहे थे।

चिकित्सकों की संख्या से प्रभावित होती है ओपीडी: सीएमएस

सीएमएस डा. विनोद चंद पांडेय का कहना है कि डा. आरसी गुप्ता अवकाश पर गए हैं। डा. एसएन सिंह कुछ देर के लिए ओपीडी में आए थे उनकी तबीयत खराब हो गई तो घर चले गए। डा. सूर्यांशु ओझा कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर लखनऊ गए हैं। सीएमएस का तर्क है कि चिकित्सकों की संख्या कम होने की वजह से ओपीडी प्रभावित रहती है। इस संबंध में सीएमओ और शासन को पत्र लिखा गया है। शनिवार को ओपीडी में 700 मरीज पहुंचे।

इनसाइड

स्क्रैप कारोबारी से बदमाशों ने 5 लाख रुपए लूटे, गन पॉइंट पर वारदात को दिए अंजाम

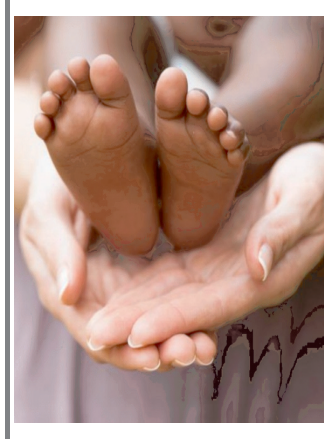

साहिबाबाद में एक स्क्रैप कारोबारी से बदमाशों ने गन पॉइंट पर 5 लाख रुपए लूट लिए। स्क्रैप कारोबारी शनिवार की देर रात फैक्ट्री से घर को वापस लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया।

साहिबाबाद। गाजियाबाद के साहिबाबाद में कारोबारी की स्क्रैप कारोबारी से बदमाशों ने 5 लाख रुपए की लूट की है। कारोबारी की शालीमार गार्डन में स्क्रैप की फैक्ट्री है। बदमाशों ने स्क्रैप कारोबारी को गोली मारने की धमकी देते हुए रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए।

फैक्ट्री से घर को लौट रहा था कारोबारी

पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत कराई है। बता दें साहिबाद के शालीमार गार्डन में एक स्क्रैप फैक्ट्री है। फैक्ट्री से रात के समय स्क्रैप कारोबारी अनस मलिक वापस घर लौट रहा था। अनस के पास रुपयों से भरा बैग था। फैक्ट्री से लौट रहे कारोबारी का बदमाशों ने पीछा किया।

5 लाख रुपए लूट ले गए बदमाश

कारोबारी अनस मलिक के अनुसार, शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे कार से घर जा रहे थे। घर से कुछ दूरी पहले ही एक कार में चार बदमाश आए और ओवरटेक करके उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने स्क्रैप कारोबारी से 5 लाख रुपए लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी। अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं लगा है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है।

15 साल से फरार हिस्ट्रीशीटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस पर हमले के मामले में था आरोपित

बलवा और पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में जमानत कराने के बाद फरार चल रहे आरोपित को मसूरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

गाजियाबाद। बलवा और पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में जमानत कराने के बाद फरार चल रहे आरोपित को मसूरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपित मेरठ के मुंडाली थाने का हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस का कहना है कि इसके अलावा एक अन्य वारंटी को भी पकड़ा गया है।

वारंटियों के खिलाफ दर्ज कई

गिरफ्तारी के बाद दोनों वारंटियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। डीसीपी जोन ग्रामीण रवि कुमार ने बताया कि मसूरी पुलिस ने दो वारंटियों मेरठ मुंडाली के गांव नगलामल का इरशाद व मसूरी नाहल का इमरान उर्फ खान शामिल हैं। डीसीपी ने बताया कि इरशाद के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी मांगने और बलवा समेत अन्य संगीन धाराओं के करीब तीन दर्जन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

मसूरी थाने में इरशाद के खिलाफ वर्ष 2008 में बलवा और पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें इरशाद जमानत कराने के बाद कोर्ट में गैर हाजिर चल रहा था। कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए, लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ सका। जांच में पता चला है कि फरारी के दौरान वह लगातार आपराधिक घटनाओं में लिप्त था।

14 वारंटी व एक वांछित दबोचा

मसूरी पुलिस उसे लगातार तलाश कर रही थी। इसी बीच थाने पुलिस सूचना मिली कि इरशाद अपने पिता का इंतकाल होने पर घर पहुंचा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम उसके घर पहुंची और उसे दबोच लिया। ग्रामीण जोन की पुलिस ने शनिवार रात अभियान चलाकर 14 वारंटी व एक वांछित को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ग्रामीण जोन रवि कुमार ने बताया कि शनिवार रात 12 बजे से रविवार सुबह आठ बजे तक चलाए गए अभियान में यह कार्रवाई हुई है।

उन्होंने बताया कि मुरादनगर पुलिस ने दो, लोनी ने चार वारंटी व एक वांछित अपराधी, भोजपुर पुलिस ने दो, मोदीनगर ने दो, निवाड़ी ने एक, क्रासिंग रिपब्लिक ने एक व वेव सिटी थाने की पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया है।

पानी बेचने को लेकर दो समुदाय के बीच हुई मारपीट, युवक पर लोहे की रॉड से किया हमला; 5 गिरफ्तार

गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित टीला मोड़ थाना क्षेत्र के गिरमा गार्डन में रविवार को दो पक्षों के बीच पानी बेचने को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में ईशु की शिकायत के बाद पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गाजियाबाद। साहिबाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के गिरमा गार्डन में दो पक्षों में रविवार को मारपीट हो गई। एक पक्ष के लोगों ने सहायक पुलिस आयुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों की तहरीर पर दूसरे पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे पक्ष की रिपोर्ट दर्ज न होने पर वह देर रात तक टीला मोड़ थाने पर हंगामा करते रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अशोक वाटिका के रहने वाले ईशु शिखरवाल ने पुलिस को बताया कि रविवार दोपहर को गरिमा गार्डन के ब्रह्म चौक के पास वह खड़ा था। तभी सद्दाम नाम के युवक ने रंजिश के चलते उस पर हमला कर दिया। आरोपित ने नेता गिरी करने की बात कहते हुए लोहे की रॉड से मारा। उसके साथ 10-15 लोग और आ गए। उन्होंने भी उसे पीटना शुरू कर दिया। उसे बचाने के लिए उसके साथी शिवम और रोहित आए तो आरोपितों ने उसे भी पीटा। उसके सिर में रोड मारकर घायल कर दिया। उसकी जान लेने की कोशिश की।

उन्होंने हमला करने वाले पांच लोगों को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस को पांचों लोगों सौंप दिया। हमला करने पर विरोध में एक पक्ष के लोगों ने राजेंद्र नगर में सहायक पुलिस आयुक्त पूनम मिश्रा के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने ईशु की तहरीर पर सद्दाम, सुहेल, शाहिद, युसुफ, गुलाम मोहम्मद, सकील, शाहरूख, अमन, सोनू ओर मोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

दूसरे पक्ष ने भी किया हंगामा

एफआइआर दर्ज होने और पांच लोगों के गिरफ्तार होने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। देर शाम को बड़ी संख्या में महिला और पुरुष टीला मोड़ थाने में हंगामा करते रहे। उन्होंने पुलिस को मारपीट का वीडियो दिखते हुए दूसरे पक्ष के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने की मांग की। सद्दाम के स्वजन ने बताया कि सद्दाम पानी बेचने का काम करता है। दूसरे पक्ष के लोग उस क्षेत्र पानी बेचने का विरोध करते हैं। उन्होंने मारपीट कर उसका पानी फेंक दिया। उन्होंने पानी फेंकने का वीडियो भी दिखाया। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तो वह शांत हो गए।

शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई

इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद पूनम मिश्रा ने कहा, पुलिस ने एक पक्ष की ओर 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे पक्ष ने भी मारपीट के वीडियो दिखाई है। वीडियो की जांच करने कर दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

साढ़े पांच लाख कीमत की 31 बकरियां चोरी, 22 दिन तक पुलिस के चक्कर काटता रहा पीड़ित

चोरी बकरियों की कीमत साढ़े पांच लाख रुपये बताई गई हैं। दीनदयालपुरी के रोहित माली का काम करने के साथ बकरी पालन करते हैं। उनका कहना है कि वह 19 जनवरी के रात परिवार के साथ मकान में सोए थे। छत पर उन्होंने 40 बकरी बांधी थीं।

गाजियाबाद। नंदग्राम थाना क्षेत्र के दीनदयालपुरी में चोरों ने 19 जनवरी की रात मकान की छत से 31 बकरियां चोरी कर लीं। चोर बराबर की छत के रास्ते आए और नशीला स्प्रे कर सो रहे युवक को बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपित मकान का दरवाजा खोलकर बकरियां चुरा ले गए।

मामले की शिकायत नंदग्राम चौकी में की गई तो पुलिस 22 दिन तक घुमाती रही। पीड़ित रिपोर्ट दर्ज करने के लिए चक्कर काटता रहा, पर पुलिसकर्मियों ने नसीहत दी कि बकरियों का बीमा क्यों नहीं कराया। बाद में थाने पर शिकायत करने पर रिपोर्ट दर्ज की गई। चोरी बकरियों की कीमत साढ़े पांच लाख रुपये बताई गई हैं। दीनदयालपुरी के रोहित माली का काम करने के साथ बकरी पालन करते हैं।

नशीला स्प्रे छिड़ककर प्रदीप को किया बेहोश

उनका कहना है कि वह 19 जनवरी के रात परिवार के साथ मकान में सोए थे। छत पर उन्होंने 40 बकरी बांधी थीं। उनकी सुरक्षा के लिए छत पर प्रदीप को सुलाया था। रात में बराबर के प्लाट से कुछ लोग छत पर आए और प्रदीप को नशीला स्प्रे छिड़ककर बेहोश कर दिया। आरोपित बकरी खोलकर सीढ़ियों के रास्ते ले गए। सुबह होने पर पुलिस कंट्रोल रूम के साथ नंदग्राम पुलिस चौकी पर शिकायत दी। आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और उन्हें लगातार घुमाती रही। वह 10 फरवरी को थाने पहुंचे तो रिपोर्ट दर्ज की गई। एसीपी नंदग्राम आलोक दुबे का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर बकरियों की तलाश की जा रही है। चोरों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

ऑटोमोबाइल विशेष

इनसाइड

परिवार की सुरक्षा से न करें खेलवाड़, कार लेने से पहले जरूर चेक करें ये 5 सेफ्टी फीचर्स

अगर आप इन दिनों एक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। किसी भी कार में इन टॉप-5 सुरक्षा फीचरों को जरूर होना चाहिए।

नई दिल्ली। हम में से ज्यादातर लोग जब कभी भी नई कार खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस और सुरक्षा से जुड़े फीचर्स पर ध्यान देते हैं। पहले जहां कार के डिजाइन, लुक और पावरट्रेन को भारत में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। अब ग्राहक इस बात का भी ध्यान दे रहे हैं कि उनकी कार हर तरह से सुरक्षित रहें और चालक के साथ-साथ पैसेंजर को भी सुरक्षा पहुंचाए। सेफ्टी फीचर्स के लिए लोग अधिक से अधिक रकम चुकाने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि, बहुत कम लोगों को पता होता है कि असल में उनकी गाड़ी पर कौन-कौन से फीचर्स होने चाहिए। इसलिए, आज हम आपको 5 ऐसे सेफ्टी कार फीचर्स (Safety Car Featurers) के बारे में बताएंगे जिनका होना बेहद जरूरी है।

1. एयरबैग (Airbags)

कार चाहे सस्ती हो या महंगी, उसमें एयरबैग का होना बेहद जरूरी है। यह दुर्घटना के समय एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान को कम करता है और चालक के साथ-साथ पैसेंजर की जान को भी बचाता है। वर्तमान में भारत में बिकने वाली ज्यादातर गाड़ियों में डुअल एयरबैग होता है, लेकिन अब सरकार ने 6 एयरबैग का होना कार में जरूरी कर दिया है।

2. एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS)

आजकल की गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर EBD के साथ ABS जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। ABS या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अचानक ब्रेक लगाने पर कार को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी के पहिये लॉक हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए ABS बहुत मददगार साबित होता है।

3. इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ESC)

ओवरस्टेयर या अंडरस्टेयर के कारण कई बार कार अपना नियंत्रण खो देती। इससे बचने के लिए आपात स्थिति के दौरान ईएससी ब्रेक लगाता है और इंजन की पावर को संतुलित करता है।

4. एडजस्टेबल स्टीयरिंग

बहुत बार स्टीयरिंग व्हील और चालक के बीच की दूरी और ऊंचाई सही नहीं रहने के कारण गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, जो बाद में जाकर दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। इस वजह से एडजस्टेबल स्टीयरिंग का कार में होना बेहद जरूरी है। यह ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील की ऊंचाई और ड्राइवर से दूरी को ठीक रखने में मदद करता है।

5. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

बेहतर कंट्रोल और ईंधन की बचत के लिए आजकल की गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) को लगाया जाता है। यह कार के हर पहिये पर लगा होता है जो कि एक सेंसर के जरिए डैशबोर्ड तक सूचनाओं को भेजता

क्या सच में गायब हो जाएंगी पेट्रोल कारें? EV या हाइड्रोजन; कौन बनेगा ऑटोमोबाइल का भविष्य

Petrol Car की जगह लेने के लिए कंपनियां तेजी के साथ इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कारों को पेश कर रही हैं। ऐसे में क्या सच में इस तरह की गाड़ियां की भविष्य में मिलेंगी इस बात से पहले इनके फायदे और नुकसान को समझ लें।

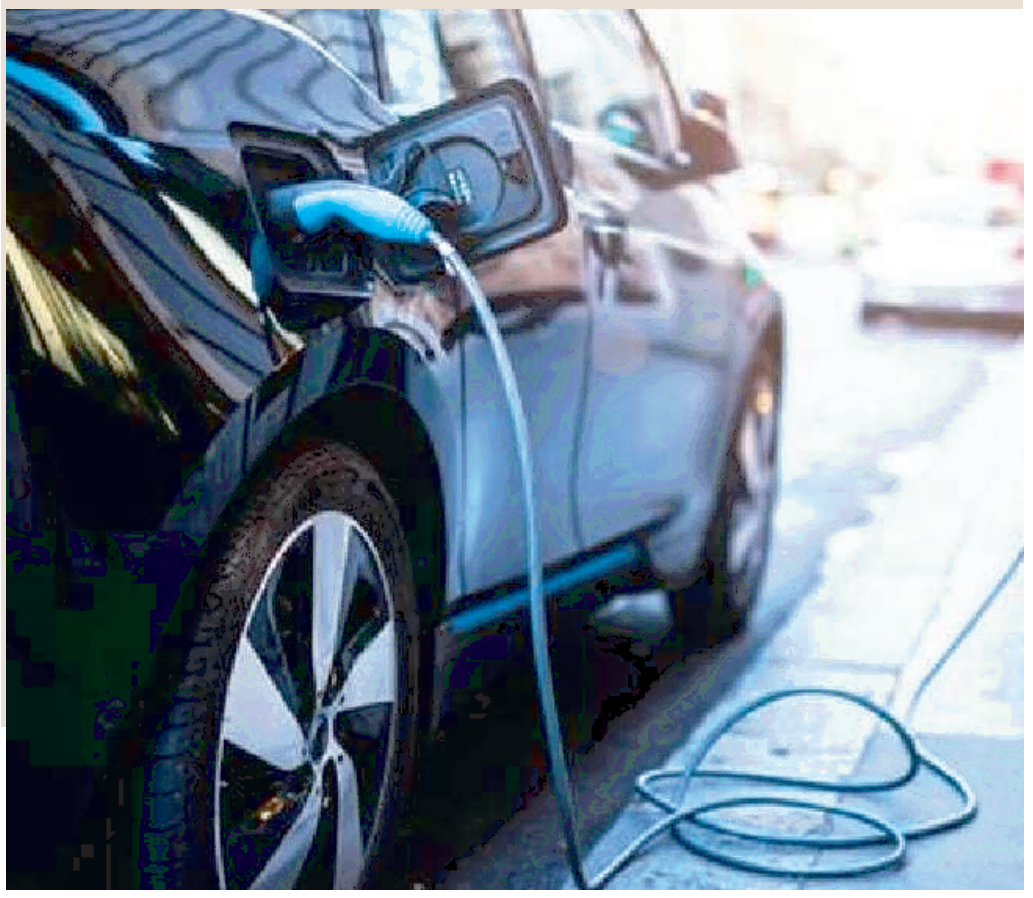

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ ICE इंजनों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इन्ही कारणों से वाहन निर्माता कंपनियां ईंधन के नए विकल्पों की तलाश कर रही हैं। बीते कुछ साल में विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन खूब बढ़ा है। यह सस्ता और कम नुकसानदायक विकल्प है। वहीं, अब एक नया हाइड्रोजन विकल्प भी सामने आया है।

हाल में हुए Auto Expo 2023 में MG Motors ने अपनी हाइड्रोजन कार Euniq 7 को पेश किया, जो हाइड्रोजन सेल के अलावा कई और खूबियों से लैस थी। वहीं, Toyota ने पहले ही अपनी Mirai कार के कॉन्सेप्ट वर्जन को पेश कर दिया है।

इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन दोनों ही गाड़ियों को भविष्य की गाड़ी के रूप में देखा जा रहा है और ये दोनों ही पेट्रोल कारों की जगह ले सकती है। पर सवाल उठता है कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक दोनों में से कौन-सी कार ज्यादा सस्ती, टिकाऊ और भरोसेमंद साबित होगी? इसलिए, आज हम इन दोनों की एक तुलना करने जा रहे हैं।

कौन-सी कार में मिलेगी ज्यादा रेंज

इसमें कोई शक नहीं है कि हाइड्रोजन कारों में रेंज ज्यादा मिलने वाली है। हाइड्रोन कारों का धनत्व ज्यादा होता है, जिससे ये कारें दूर तक चलाई जा सकती है। वर्तमान में पेश किए गए मॉडलों के आधार पर टोयोटा मिराई को एक बार चार्ज करने पर 600 किमी तक की रेंज दे सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों में अब तक अधिकतम 250 किमी तक की रेंज देखई गई है।

बजट फ्रेंडली

ज्यादा रेंज के साथ ही गाड़ियों को बजट फ्रेंडली भी होना जरूरी है। इस आधार पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक मिडिल क्लास फैमिली के बजट में ज्यादा आसानी से आ सकती है, जबकि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों में लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से इनकी कीमतें भी अधिक होंगी। वहीं, बाद के समय में कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन कारों को कम कीमत पर लाना होगा।

रिफिल में लगने वाला समय

इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन दोनों गाड़ियां को अगर पेट्रोल गाड़ियों की जगह लेनी है तो इसे रिफिल करने में कम समय लगना चाहिए। एक तरफ जहां इलेक्ट्रिक कारों अगर एक बार डिस्चार्ज हो गई तो इसे फुल चार्ज होने में 4 से 8 घंटे का समय लगता है। वहीं, हाइब्रिड कारों में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। फ्यूल स्टेशन पर एक किलो हाइड्रोजन को रिफिल करने में बस 5 से 10 मिनट कसमी लगता है, जो काफी हद तक पेट्रोल रिफिलिंग के समान ही है।

दिव्यांगजनों के लिए गाड़ी पंजीकरण होगा आसान, सरकार जल्द करेगी ये व्यवस्था

MoRTH ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राज्य के अधिकारी इस तरह के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा शर्तों में एक दिव्यांग व्यक्ति शामिल होना अनिवार्य है जो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के साथ ड्राइवर को काम पर रखा हो।

नई दिल्ली। भारत सरकार दिव्यांग लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करती है। इसी क्रम में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राज्यों से दिव्यांगजन कैटेगरी में आने वाले लोगों को जरूरी टेक्स लाभ की गुजारिश की है। अभी तक केवल नए वाहन खरीद पर यह लाभ मिलता था।

केंद्र सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में मेंशन किया है कि दिव्यांग व्यक्ति जो वाहन के मालिक हैं और ड्राइवर को किराए पर लेते हैं, उन्हें ₹दिव्यांगजन₹ श्रेणी के तहत वाहन पंजीकरण प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वाहन का स्वामित्व ₹दिव्यांगजन₹ श्रेणी के तहत पंजीकरण के लिए निर्णायक कारक होगा। इससे वाहन गाड़ी का प्रकार। MoRTH ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राज्य के अधिकारी इस तरह के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, शर्तों में एक दिव्यांग व्यक्ति शामिल होना अनिवार्य है जो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के साथ ड्राइवर को काम पर रखा हो। दूसरी शर्त यह है कि अगर दिव्यांगजन नई गाड़ी खरीदने में असमर्थ है और वह इस कैटेगरी से आवेदन करता है तो उसका पंजीकरण मान्य होगा। इसके अलावा भी सर्कुलर में कई निर्देश दिए गए हैं।

इंडियन मार्केट में कारों की तुलना में टू-व्हीलर्स क्यों फेमस? असल वजहों के बारे में समझें

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जहां बेचे गए कुल वाहनों की अधिकांश बिक्री पैसेंजर वाहनों द्वारा कवर की जाती है और उनमें से एक बड़ा हिस्सा दोपहिया वाहनों का हैं। कारों की तुलना में टू-व्हीलर्स को लोग अधिक महत्व देते हैं।

नई दिल्ली। भारत में इस समय कारों की बिक्री में इजाफा देखने को मिला है। आप खुद ही आप पास के घरों में खड़ी कारों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि, जिनके भी घर कार होगी उनके घर दोपहिया वाहन जरूर देखने को मिलेगा। इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं उन 3 वजहों के बारे में जहां आपको यह पता चलेगा कि कारों की तुलना में टू-व्हीलर्स इंडियन मार्केट में क्यों फेमस हैं

बेहतरीन माइलेज

कारों की तुलना में मोटरसाइकिल की माइलेज भी अधिक होती है। अगर कार औसतन 25 की माइलेज देती है तो टू-व्हीलर भी 60-70 तक की औसतन माइलेज देने में सक्षम है। यही वजह है कि भारत में अधिकतर लोग चार पहिया की तुलना में दोपहिया वाहन खरीदना अधिक पसंद करते हैं। इस समय एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस आने वाली मोटरसाइकिलों जिसमें अधिक सीसी का इंजन लगा हुआ होता है उसकी औसतन माइलेज 20-30 Kmpl होती है।

प्रदूषण

पर्यावरण के नजरिए से भी दोपहिया वाहन चार पहिया वाहन की तुलना में बेहतरीन होते हैं, क्योंकि चार पहिया वाहन अधिक ईंधन खाते हैं और उससे अधिक पॉल्यूशन भी निकलता है, वहीं दोपहिया वाहन हैं बहुत कम ईंधन खर्च होने के कारण उससे होने वाली पॉल्यूशन की मात्रा कम होती है। इसलिए, पर्यावरण के लिहाज से टू-व्हीलर बेस्ट होती हैं।

किफायती दाम

दोपहिया वाहन कार की तुलना में बेहद सस्ते होते हैं। जिस वजह से एक मध्यम वर्गीय परिवार और निचला मध्यम वर्गीय परिवार भी इसे खरीद पाता है। भारत के बाज़ार में लगभग 40,000 रुपए की शुरुआती क़ीमत से दोपहिया वाहनों की बिक्री शुरू हो जाती है। इसके अलावा, इन वाहनों के लिए बीमा बहुत कम लागत पर आता है। दोपहिया वाहनों की सबसे ख़ास बात यह होती है कि इनकी री सेल क़ीमत भी बहुत अधिक होती है। साथ ही इनका माईलेज भी कार की तुलना में कहीं बेहतर होता है।

इस मौसम में सबसे अधिक परेशान करती है कार के अंदर की धुंध, इन उपायों से मिलेगा चुटकियों में समाधान

आपके ड्राइविंग अनुभव को धुंधली स्क्रीन काफी हद तक खराब कर देती है। इससे गाड़ी चलाते समय सामने देखना काफी मुश्किल हो जाता है। धुंध सिर्फ बाहर ही नहीं आपके कार के अंदर भी परेशान करती है। इसके लिए आपको इन चुनिंदा बातों का ख्याल रखना चहिए।

नई दिल्ली। इस समय ठंड काफी तेजी से बढ़ रही है।सुबह के समय कोहरा काफी अधिक हो रहा है, जिससे गाड़ी चलाते समय सामने देखना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये परेशानी कार के अंदर भी होती है। अगर आपके कार के अंदर भी ठंड के मौसम में धुंध भर जाती है तो आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिससे आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके ड्राइविंग अनुभव को धुंधली स्क्रीन काफी हद तक खराब कर देती है। सबसे अधिक दिक्कत इस समय होती है। कोहरे के कारण आप कार के बाहर का देख नहीं सकते हैं। धुंध सिर्फ बाहर ही नहीं आपके कार के अंदर भी परेशान करती है। इसके लिए आपको इन चुनिंदा बातों का ख्याल रखना चहिए।

डिफॉग बटन का इस्तेमाल करें

अगर आप इस बात से अनजान हैं तो अपनी कार के अंदर आप विंडशील्ड को डिफॉग करने के लिए गाड़ी के अंदर दिए गए डिफॉग बटन का इस्तेमाल करें। ये बटन आपके कार के अंदर आता है। इसको दबाने के बाद हवा सीधे विंडशील्ड तक पहुंच जाती है।

एसी को ऑन करें

कार में जैसे ही बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद फॉग महसूस होने लगता है, जिसके कारण आप बाहर का देख नहीं सकते और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इसके लिए आप कार में एसी को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद लिंट-फ्री कपड़े से स्क्रीन को पोछ लेना चाहिए, ताकि आपको दिखाई देने लगे। इसके कारण कार के अंदर की धुंध भी गायब हो जाती है।

खिड़की को नीचे करें

कार के अंदर से धुंध को बाहर करने के लिए खिड़की को नीचे करना एक अच्छा ऑप्शन है। इससे बाहर की हवा अचानक आपकी कार के अंदरुनी हिस्सो को भर देती है, इसके कारण ही अंदर का तापमान बाहर के तापमान की तरह हो जाता है।

नदी जल शक्ति से विकास का नया दौर

डा. जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज- एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ 1000 करोड़ रुपये से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में नदी जल मार्ग की क्षमता के लाभ लेने के नए दौर का सूत्रपात हो रहा है। वस्तुतः देश में एक लम्बे समय से जल परिवहन में शामिल अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय नौवहन के विकास की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। जिन जल मार्गों को देश के प्राकृतिक पथ कहा जाता है वे अतीत में भारतीय परिवहन की जीवन रेखा हुआ करते थे। ये जल मार्ग शताब्दियों से कारोबार, उद्योग और आर्थिक शक्ति का मुख्य आधार हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद जलमार्गों की लगातार उपेक्षा हुई। खासतौर से बीती एक शताब्दी में भारत में जल परिवहन क्षेत्र बेहद उपेक्षित होता चला गया। देश की आजादी के बाद भी सडक़, रेल और वायु मार्गों की होड़ में परम्परागत जीवनदायी जलमार्ग नजरअंदाज होते गए। ज्ञातव्य है कि देश में 7500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट और करीब 14500 किलोमीटर संभावित नौवहन योग्य जलमार्ग है। देश को इस विशाल नदी मार्ग पर हमेशा बहती रहने वाली नदियों, झीलों और बैकवाटर्स का उपहार भी मिला हुआ है। गौरतलब है कि देश खासतौर से 2014 के बाद, नदी जल मार्गों की प्राचीन शक्ति का उपयोग करने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ा है। देश की बड़ी नदियों में जलमार्ग विकसित करने के लिए नया कानून और विस्तृत कार्ययोजना लाई गई है। 2014 में देश में केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, अब देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं और लगभग दो दर्जन पहले से ही चालू हैं। इसी तरह, नदी जलमार्ग के माध्यम से कार्गो परिवहन में 8 साल पहले 30 लाख मीट्रिक टन से 3 गुना वृद्धि हुई है। जलमार्ग पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अच्छे हैं और पैसे की भी बचत करते हैं। जलमार्गों के संचालन की लागत सडक़ मार्गों की तुलना में ढाई गुना कम है और रेलवे की तुलना में एक तिहाई कम है।

यही कारण है कि चीन और अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने जैसे-जैसे विकास की ओर कदम बढ़ाए, वैसे-वैसे वे अपने जल मार्गों का अधिक उपयोग करने लगे। कई यूरोपीय देश अपने कुल माल और यात्री परिवहन के लिए जल परिवहन का बहुतायत से उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, यूरोप के कई देश आपस में इसी साधन से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जल मार्गों को अपनी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बना लिया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 11 और 12 नवंबर को वाराणसी में पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन के दौरान यह बात उभरकर सामने आई कि भारत की नई लॉजिस्टिक नीति 2022 और गतिशक्ति योजना का आगाज अभूतपूर्व रणनीतियों के साथ हुआ है और इनके तहत जल परिवहन के विकास से लॉजिस्टिक कास्ट के बोझ को घटाया जा सकता है । इसी तरह से मेरीटाइम इंडिया मिशन 2030 देश के बंदरगाहों के विकास और लॉजिस्टिक लागत घटाकर समुद्री अर्थव्यवस्था से देश को लाभान्वित करने से संबंधित है। मैटीराइम इंडिया समिट 2021 में यह रेखांकित हुआ है कि भारत बंदरगाह विकास की नई रणनीति से सागरमाला परियोजना के तहत 574 से अधिक परियोजना के लिए वर्ष 2035 तक 82 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इससे समुद्री नौवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी, जलमार्गों का विकास किया जाएगा। इस समय इस मिशन के तहत बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइटहाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ हैं।

इनमें से सरकार 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन का विकास करने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में अब और राष्ट्रीय जलमार्गों से देश की आर्थिक-सामाजिक तस्वीर को संवारने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जाने होंगे। भारत में विकासशील जलमार्गों की निरंतर विकास प्रक्रिया एक विकसित भारत के निर्माण के लिए मजबूत कनेक्टिविटी तथा देश के व्यापार और पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए जरूरी है। चूंकि भारत में हजारों किलोमीटर के जलमार्ग नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता है। अतएव भारत में जो 125 से ज्यादा नदियां और नदी धाराएं हैं, वे लोगों और सामान के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जा सकती हैं और ये वाटर-वे, भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को भी बढ़ाने में मदद करते हुए दिखाई दे सकती है। अब जल परिवहन का बुनियादी ढांचा तैयार करने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारी भरकम संसाधन जुटाने के लिए पीएम गतिशक्ति योजना और नई लॉजिस्टिक नीति के तहत प्रावधानों के कारगर क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा। जल परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए इस बात की वैधानिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी कि विभिन्न नदी तटीय इलाकों के कारखाने तथा अन्य उपक्रम अपनी माल ढुलाई में एक खास हिस्सा जलमार्गों को दें।

जल मार्ग उपयोग करने वालों को कुछ सब्सिडी भी दी जानी होगी। इससे अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय जहाजरानी दोनों को बढ़ावा मिलेगा, सस्ते में परिवहन होगा और उद्योग कारोबार को प्रोत्साहन मिलेगा। खासतौर से खतरनाक सामग्री और गैस, पेट्रोल या रसायनों का एक हिस्सा जल परिवहन को आवश्यक रूप से हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करना होगा। हम उम्मीद करें कि वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज और कई अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ भारत से नदी जलमार्ग के क्षमताओं के उपयोग के नए दौर की शुरुआत आम आदमी और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभ पर होगी। साथ ही पीएम गतिशक्ति योजना, नई लॉजिस्टिक नीति 2022 और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत अंतर्देशीय जलमार्गों को भारी प्रोत्साहन देने की रणनीति से जल मार्गों के प्रभावी व्यावसायिक उपयोग, सस्ते जल परिवहन और जलमार्गों पर पर्यटन विकास के नए अध्याय लिखे जा सकेंगे। भारत में जलमार्गों के विकास से ढुलाई लागत यानी लॉजिस्टिक कास्ट को घटाकर भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा । ऐसे में नदी जल मार्ग भारत की नई सामथ्र्य बनते हुए दिखाई देंगे । ये विकास के मार्ग बनेंगे।

> हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज- एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ 1000 करोड़ रुपये से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में नदी जल मार्ग की क्षमता के लाभ लेने के नए दौर का सूत्रपात हो रहा है। वस्तुतः देश में एक लम्बे समय से जल परिवहन में शामिल अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय नौवहन के विकास की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

संपादक की कलम से

महंगाई डायन कब जात है

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुद्रास्फीति, महंगाई की दर 5.3 फीसदी रह सकती है। फिलहाल यह दर 6 फीसदी से अधिक है, जो तय लक्ष्मण-रेखा लांघती लग रही है। अलबत्ता खतरनाक स्थिति नहीं है। एक तरफ महंगाई को काबू में रखने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। अब रेपो रेट 6.50 फीसदी 2018 के बाद सबसे ऊंची दर है। रिजर्व बैंक का अर्थशास्त्र कहता रहा है कि इससे महंगाई को कम किया जा सकता है। पेशेवर अर्थशास्त्र इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि बाज़ार में पैसा नहीं होगा, तो मांग घटेगी। मांग कम होने का सीधा असर आपूर्ति और उत्पादन पर पड़ता है। उससे अर्थव्यवस्था की विकास दर भी प्रभावित होकर कम होती है। रोजग़ार के अवसर भी कम हो जाते हैं।

बैंकों के ऋण जरूर महंगे हो जाते हैं। उनसे भी आम आदमी ही प्रभावित होता है। अच्छा है कि 2023-24 में महंगाई कम हो सकती है, क्योंकि इस साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और 2024 में तो निर्णायक लोकसभा चुनाव होने हैं। इधर कुछ नए सर्वेक्षण सामने आए हैं, जिनमें महंगाई को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी आंका गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में और भी गिरावट आ सकती है, नतीजतन मुद्रास्फीति भी घट सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि कच्चे तेल की कीमतें 40 डॉलर प्रति बैरल कम हो चुकी हैं, फिर भी उनका फायदा आम उपभोक्ता को नहीं दिया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल कंपनियों को पत्र लिख कर आग्रह किया था कि कंपनियों के घाटे की लगभग भरपाई की जा चुकी है और कच्चे तेल की कीमतें भी नियंत्रण में हैं, लिहाजा आम उपभोक्ता के लिए कीमतें कम की जाएं।

लेकिन तेल कंपनियों ने केंद्रीय मंत्री के आग्रह की भी परवाह नहीं की और पेट्रोल, डीजल के दाम यथावत हैं। महंगाई, मुद्रास्फीति की दर बढऩे में तेल की बड़ी भूमिका है। कच्चा तेल 135-140 डॉलर प्रति बैरल भी हुआ है और 30-40 डॉलर तक भी लुढक़ा है और अब 90-94 डॉलर प्रति बैरल के बीच में घूम रहा है। भारत अपनी मुद्रा में रूस से भी सस्ता तेल खरीद रहा है। सवाल है कि तेल सस्ता होने पर आम उपभोक्ता को पेट्रोल, डीजल आदि सस्ते क्यों नहीं मिलते? तेल कब तक आम आदमी का तेल निकालता रहेगा? बेशक रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 2023-24 के दौरान मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में आने का भरोसा दिलाने की कोशिश की है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में 'नियंत्रित अर्थव्यवस्था' नहीं है। यदि किसी वस्तु के दाम महंगे कर दिए गए, तो उन्हें तेल की कीमतें घटने या सामान्य हालात होने के बावजूद सस्ता नहीं किया जाएगा। एक और उदाहरण दूध का है। यदि उसके दामों पर नियंत्रण और निगाह के लिए कोई नियामक एजेंसी तय नहीं की गई, तो उसकी स्थिति भी तेल जैसी अनियंत्रित हो जाएगी। बेशक खुदरा और थोक महंगाई की दरें फिलहाल कम हैं। सब्जियों के दाम स्थिर हैं, लेकिन आटा, चावल, अरहर की दाल, उड़द और चना दाल, राजमां और सरसों का तेल आदि वस्तुएं महंगी हुई हैं।

14 फरवरी का इतिहास

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार फरवरी 14 किसी वर्ष में दिन संख्या 45 है। भारत और विश्व इतिहास में 14 फरवरी का अपना ही एक खास महत्व है, क्योकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गईं हैं। आईये जानते हैं 14 फरवरी की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ जिन्हे जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एकत्रित तथ्य ऐसे होंगे जैसे : आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आजादी, नई तकनिकी का अविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस इत्यादि।

World Events

14 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएँ विश्व में ⚡

वर्ष	घटना/वारदात/वृत्तांत
1735	महान पीटर की बेटी के सम्मान में सेंट अण्णा को रूस में स्थापित किया गया।
1747	खगोल विज्ञानी जेम्स ब्रैडली ने रॉयल सोसाइटी, लंदन के लिए अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति को देने की खोज प्रस्तुत की।
1779	अंग्रेजी खोजकर्ता जेम्स कुक कीलेकेकुआ के पास मारे गए थे जब उन्होंने हवाई द्वीप के शासक प्रमुख कलानी पु यू का अपहरण करने की कोशिश की थी।
1814	वौचैप्स का युद्ध में फ्रांस के नेपोलियन I ने वॉन ब्लूचर के खिलाफ विजय प्राप्त की।
1820	वियतनाम में मिन्ह मांग का शासन शुरू हुआ।
1835	लैटरडेय संत आंदोलन के बारह के मूल कोरम के सदस्यों को तीन गवाहों द्वारा चुना गया था।
1859	ओरेगन को 33 वें अमेरिकी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया।
1876	आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एलीशग्रे ने प्रत्येक ने टेलीफोन के लिए एक पेटेंट दायर किया, जिसके बारे में एक विवाद शुरू हुआ।
1899	अमेरिकी कांग्रेस ने वोटिंग मशीन का उपयोग कर शुरू किया।
1912	पहली डीजल पनडुब्बी लंदन के पास ग्रोटन शहर में बनाई गई।
1919	वर्तमान समय के बिरोजा, बेलारूस के पास पोलिश-सोवियत वार्टूक स्थान का पहला गंभीर सशस्त्र संघर्ष।
1924	कम्प्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी ने खुद का नाम बदलकर इंटरनैशनल बिज़नेस मशीन रखा, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है।
1938	सिंगापुर में ब्रिटिश नौसैनिको ने ऑपरेशन शुरू किया।
1939	जर्मन युद्धपोत बिस्मार्क को शुरू किया गया।
1942	बिलिन नदी की लड़ाई बर्मा में शुरू हुई।
1943	द्वितीय विश्व युद्ध : जनरल हंस-जुर्गन वॉन अर्निम के पांचवें पैंजर सेना ने ट्यूनीशिया में मित्र देशों की स्थिति के खिलाफ एक ठोस हमला किया।

जोशीमठ का हिमालय के लिए संदेश

हिमालयी राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार पर दबाव डाल कर पर्वतीय विकास के लिए अलग विकास मॉडल बनवाने का प्रयास करें और केंद्र सरकार एसजेड कासिम की अध्यक्षता वाली कमेटी की रपट का अध्ययन करके और वर्तमान में नीति आयोग द्वारा बनाए गए हिमालयी क्षेत्रीय परिषद को इस काम पर लगाना चाहिए और विश्वव्यापी अनुभवों के आधार पर पर्वतीय विकास का पर्यावरण मित्र मॉडल विकसित करना चाहिए'

जोशीमठ की त्रासदी ने पूरे देश को अचंभित ही नहीं किया है बल्कि हिमालय में विकास की गाड़ी की दिशा पर भी अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। सदियों पुराना शहर आखिर धंस क्यों रहा है। वैसे तो आजादी के बाद से ही हिमालय के लिए विकास योजना को इस क्षेत्र की भौगोलिक और पर्यावरण की विशिष्टता के कारण अलग दृष्टि से देखा जाने लगा था। इसी कारण योजना आयोग में भी हिमालय का अलग सेल हुआ करता था। अब नीति आयोग में भी हिमालयन क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है ताकि हिमालय की विशिष्ट नाजुक स्थिति को ध्यान में रख कर विकास गतिविधियों का खाका बनाया जा सके। 1992 में डा. एसजेड कासिम की अध्यक्षता में योजना आयोग ने हिमालय में विकास की दिशा और दशा को निर्धारित करने के लिए एक ग्रुप का गठन किया था जिसकी रपट 1992 में ही आ गई थी। किन्तु इस तरह की तमाम कोशिशों के बावजूद हिमालयी क्षेत्र में विकास के लिए कोई अलग मॉडल विकसित नहीं किया जा सका, जिसका मुख्य कारण यह रहा है कि हिमालयी संसाधनों पर तो योजनाकारों की नजर रही, किन्तु उनके दोहन या दोहन के तरीकों के कारण कितनी विपदाएं हमें घेर सकती हैं और देश के लिए हिमालय द्वारा की जा रही पर्यावरणीय सेवाओं पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इस ओर किसी ने नहीं सोचा। बातें तो हुई किन्तु जमीन पर कुछ उतर नहीं सका। इसी का नतीजा है कि हिमालय में मनमानी उखाड़ पछाड़ विकास के लिए की गई जो अब तक जारी है और कमेटियों या हिमालयी विकास को दिशा देने के लिए बनाए गए ग्रुपों की संस्तुतियां धूल फांक रही हैं। जो लोग हिमालय के साथ मनमानी छेड़छाड़ का विरोध करते हैं उनको विकास विरोधी ठहरा कर चुप करवाने के प्रयास होते रहते हैं। मामला एक जोशीमठ का नहीं है, हिमालय में जहां भी अंधाधुंध विकास का मॉडल लागू किया गया है वहां कमोबेश इसी तरह की समस्याएं सामने आई हैं।

किन्तु उनको लीपापोती वाली भाषा से टालने का काम ही किया गया है। समाधान तलाशने की ओर देखा नहीं गया है। हिमालय वासी स्वयं भी इस मामले में ज्यादा जागरूक नहीं रहे हैं। विकास के अंध पैरोकारों के दबदबे ने विरोध के स्वरों को दबा दिया। पर्यावरणीय दृष्टि से कुछ सावधानियां प्रयोग करने के लिए भी जो छोटे-मोटे प्रावधान हुए हैं उनको भी लागू करने की व्यवस्थाएं इतनी लचर और प्रोजेक्ट लागू करने वालों को अंधी छूट देने वाली साबित हुई हैं जिससे उन प्रावधनों का महत्व ही समाप्त हो जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जनसुनवाई कभी भी लोगों को जागरूक करके नहीं होती है बल्कि कोशिश की जाती है कि लोगों

को कम से कम पता लगे ताकि योजना निर्माता अपने समर्थकों को इकट्ठा करके योजना के हक की बातों को आगे लाकर अपना रास्ता साफ कर सकें। प्रभाव आकलन का काम परियोजना निर्माताओं द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाता है। जाहिर तौर पर निर्माता परियोजना से खतरों को कम करके दिखाता है। परियोजना प्रभाव आकलन रिपोर्ट स्वतंत्र एजेंसी से बनवानी चाहिए। मौके पर निर्माण कार्य कैसे चल रहा है, कोई नहीं देखता। यहां तक कि निर्माण कार्यों में निकलने वाले मलबे की डम्पिंग करने के प्रावधानों का खुला उल्लंघन होता है किन्तु कोई नहीं सुनता। हिमालय में बन रही सडक़ों या विद्युत परियोजनाओं में ऐसी घटनाएं हर कहीं सामान्य बात बन गई हैं। निर्माण स्थलों पर वनों की स्वीकृति से कई गुणा ज्यादा तबाही की जाती है किन्तु कोई नहीं देखता। कुछ प्रोजेक्टों पर जुर्माने भी लगे हैं किन्तु फिर भी मनमानी कहां रुकती है। गढ़वाल के चंबा से भी कुछ मकान धंसने की खबरें आ रही हैं।

उत्तराखंड में और भी कई इलाके खासकर बिजली प्रोजेक्टों और बड़ी खुली फोरलेन सडक़ों के कारण खतरे में आ रहे हैं। हिमाचल भी इस तरह की त्रासदी से बचा नहीं है। प्रदेश में 450 के करीब जल विद्युत परियोजनाएं बन चुकी हैं, जिनसे 12000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकार की 27000 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है। इन परियोजनाओं से जगह-जगह बस्तियों को खतरा पैदा हुआ है। नाथपा झाकड़ी परियोजना की सुरंग के ऊपर बसे नाथपा, कंडार और निगुल्सेरी गांव धंसने लगे हैं। किन्नौर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर कड़छम वांगतू प्रोजेक्ट सुरंगें गुजरने के कारण उर्नी ढांक में एक स्थाई भूस्खलन बन गया है। जंगी-ठोपन परियोजना का कार्य अभी चल रहा है जिससे जंगी, रारंग, अक्पा और खदरा गांव को खतरा पैदा हो गया है। भरमौर में बन रही होली-बजोली परियोजना की टनल में दरार आने से इन्दौता गांव को भारी नुकसान हुआ है। जमीन धंस रही है, कई मकानों में दरारें आ गई हैं। हिमाचल में चार फोरलेन सडक़ें बन रही हैं। उनके निर्माण में भी नुकसान हो रहा है जिसका कोई जायजा नहीं लिया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि हिमालय में बड़े पैमाने के निर्माण कार्य बहुत सावधानी से किये जाने चाहिए और इसके लिए पर्वतीय विकास का अलग मॉडल विकसित किया जाना चाहिए जिसके लिए हिमालयी क्षेत्रों से लंबे समय से आवाजें उठाई जा रही हैं, किन्तु कोई परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है।

हिमालय में करणीय और अकरणीय गतिविधियों की सूची बननी चाहिए और निर्माण कार्यों एवं उद्योग स्थापना, खनन आदि कार्यों में उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हिमालयी राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार पर दबाव डाल कर पर्वतीय विकास के लिए अलग विकास मॉडल बनवाने का प्रयास करें और केंद्र सरकार एसजेड कासिम की अध्यक्षता वाली कमेटी की रपट का अध्ययन करके और वर्तमान में नीति आयोग द्वारा बनाए गए हिमालयी क्षेत्रीय परिषद को इस काम पर लगाना चाहिए और विश्वव्यापी अनुभवों के आधार पर पर्वतीय विकास का पर्यावरण मित्र मॉडल विकसित करना चाहिए, ताकि विकास की अंधी दौड़ में होने वाले स्थायी नुकसानों से बचा जा सके और टिकाऊ विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

जरूरी है सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था

प्रो. सुरेश शर्मा

हालांकि यह सही है कि वर्तमान में ज्ञान के प्रचार-प्रसार में संचार, तकनीकी संसाधनों का बहुत विस्तार हुआ है, परंतु पुस्तक, पत्र-पत्रिका तथा समाचार पत्र पढऩे का अपना ही आनंद है। इससे चिंतन, मनन तथा स्व-अध्ययन की आदत का विकास होता है तथा व्यक्ति बहुत सी विकृतियों तथा बुरी आदतों से दूर रह सकता है। समाज में एक स्वस्थ, सुंदर तथा अर्थपूर्ण वातावरण स्थापित करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार यदि चाहे तो बजट का प्रावधान कर सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना के लिए योजना बना सकती है'

हिमाचल प्रदेश में नवगठित सरकार द्वारा सत्र 2023-2024 के लिए अपना पहला बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक बजट प्रदेश तथा देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं तथा लोगों को बजट से बहुत आशाएं एवं अपेक्षाएं होती हैं। हिमाचल सरकार की ओर से बजट निर्धारण में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। लोकतन्त्र में योजनाओं के निर्माण में लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनता की मांगों, सरकार के वादों, विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार इस समय सत्र 2023-24 के बजट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। प्रत्येक सरकार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप आर्थिक संतुलन बनाते हुए लोकहित में प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाएं बनाती है। पठन-पाठन, अध्ययन किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा के बिना यह जीवन निरर्थक है क्योंकि ज्ञान-विज्ञान के आधार पर ही हमारा जीवन अर्थपूर्ण है अन्यथा अनपढ़ व्यक्ति तो पशु समान ही है।

ज्ञानार्जन के लिए पुस्तकों तथा पुस्तकालयों की उपलब्धता होना अति आवश्यक है। मानसिक, बौद्धिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ चिन्तन कर स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। शिक्षण के साथ-साथ सामाजिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय विविध ज्ञान एवं जानकारियां होना अति आवश्यक है। वर्तमान में बच्चों, युवाओं तथा वृद्धों के स्वास्थ्य, मनोरंजन, शारीरिक फिटनेस के लिए शहरों तथा गांवों में बहुत संसाधन उपलब्ध हैं, परन्तु स्व-अध्ययन तथा नवीन ज्ञान प्राप्त करने के सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों का बहुत अभाव है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं, सामान्य नागरिकों तथा वृद्धजनों को छोटे शहरों तथा गांवों में अध्ययन के लिए सार्वजनिक सुविधा न के बराबर है। हालांकि प्रदेश में अनेक स्थानों पर विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पुस्तकालयों को सार्वजनिक बना दिया गया है ताकि लोग वहां बैठ कर पढ़ सकें, लेकिन आमजन इसे संस्थानों की कार्यप्रणाली में अवरोध तथा दखल ही समझता है। इसलिए वहां भी पाठकों, अध्ययनकर्ताओं की संख्या न के बराबर ही होती है। समाज में जहां खेलकूद तथा मनोरंजन के अनेक संसाधन उपलब्ध हैं, वहीं पर वर्तमान में ज्ञानार्जन तथा स्व अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सामुदायिक पुस्तकालय एवं वाचनालय होना वर्तमान की आवश्यकता है। आज इसकी सरकारी व्यवस्था न होने के कारण शहरों तथा गांवों में बहुत से लोगों ने निजी पुस्तकालय, वाचनालय तथा अध्ययन कक्ष शुरू कर अच्छी सुविधाएं देकर व्यावसायिक रूप देकर अच्छी धनराशि कमाना शुरू कर दिया है। इन निजी पुस्तकालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा तैयारी कर रहे हैं। सामाजिक रूप से जहां यह एक अच्छी बात है, वहीं पर सरकार तथा उसके अधीन सम्बन्धित विभाग अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकते। आवश्यक है कि जहां सरकारी पुस्तकालय चल रहे हैं, उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जाए। उनमें सीटिंग कपैसिटी बढ़े तथा जलपानगृह तथा शौचालयों आदि की ठीक व्यवस्था हो। छोटे शहरों तथा ग्रामीण परिवेश में पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की सुविधा होनी चाहिए। बजट में प्रत्येक पंचायत में एक सार्वजनिक पुस्तकालय या वाचनालय होना वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसका संचालन पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग या महिला एवं समाज कल्याण के अधीन हो सकता है तथा उपरोक्त कोई भी विभाग इस नवीन कार्य का स्वप्न लेकर इसे साकार करने के लिए पहल कर सकता है।

प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालय में ज्ञान विज्ञान, इतिहास, लोक संस्कृति, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, इतिहास, धार्मिक संस्थान, कला-संस्कृति, लोक संस्कृति, मानवीय मूल्यों, राष्ट्रीय तथा नागरिकता के मूल्यों के विकास के लिए पर्यटन के लिए सामान्य पुस्तकों के साथ कम से कम दो समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, रोजगार समाचार पत्र उपलब्ध हों। अध्ययन के लिए उपयुक्त एवं सुंदर वातावरण हो, बैठने की व्यवस्था, दृश्य एवं श्रव्य संसाधन, जलपान तथा शौचालय की व्यवस्था होना इसे और अधिक उपयोगी बना सकता है। अच्छे पुस्तकालयों तथा वाचनालयों से लोगों का बौद्धिक विकास होता है, युवाओं में सृजनात्मकता तथा रचनात्मकता बढ़ती है, वृद्धों को आध्यात्मिक शांति मिलती है तथा अच्छी आदतों का विकास होता है। युवाओं को अध्ययन सामग्री सुगमता एवं सरलता से प्राप्त हो जाती है।

ब्रीफ न्यूज

बाजार में 'हिंडनबर्ग इफेक्ट', उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 224 अंक चढ़ा, निफ्टी लाल निशान पर बंद

नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। कंपनी के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगा। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयरों में बढ़त दिखी। अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बाजार में जारी उठा-पटक जारी है। गुरुवार के कारोबारी सेशन में उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 224.16 अंकों की बढ़त के साथ 59,932.24 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 5.90 अंकों की गिरावट के साथ 17610.40 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 156 अंकों की मजबूती के साथ 40669 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। गुरुवार को बाजार में निचले स्तरों पर खरीदारी दिखी। अदाणी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर करीब 27 फीसदी की गिरावट के साथ 1565 रुपये के स्तर पर बंद हुए। पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में यह 1495 रुपये तक फिसला। यह कंपनी के पिछले 52 हफ्तों का न्यूनतम स्तर है। कंपनी के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगा। अदाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट का बड़ा कारण सिटी ग्रुप की तरफ से लिया गया फैसला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिटी ग्रुप ने अदाणी सिक्योरिटीज के मार्जिन लोन पर रोक लगाने का फैसला किया है। इससे पहले क्रेडिट सुईस ने अदाणी समूह के बॉन्ड को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसके बाद सिटी ग्रुप के फैसले की खबरें आईं। इन खबरों के बाद अदाणी समूह के ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट लगा और अधिकतर स्टॉक्स 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गए। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के शेयरों में बढ़त दिखी। बजट 2023-24 में सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने के बावजूद आईटीसी के शेयरों में करीब 5 फीसदी की तेजी दिखी। गुरुवार को यह 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

बायजू ने करीब 1500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, कंपनी ने बताई छंटनी की यह बड़ी वजह

नई दिल्ली। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि बायजू ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग का हवाला देते हुए करीब 1,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। एडटेक यूनिकॉर्न बायजू ने करीब 1,500 कर्मचारियों की छंटनी की है। छंटनी ने मुख्य रूप से डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन कार्यक्षेत्र से कर्मचारियों को प्रभावित किया है। अक्तूबर में बायजू ने करीब 2,500 कर्मचारियों की छंटनी की थी, जो उसके कार्यबल का 5 फीसदी था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। मामले की जानकारी रखने वाले चार लोगों ने बताया कि बायजू ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग का हवाला देते हुए करीब 1,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बायजू के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बायजू रवींद्रन ने अक्तूबर में कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि नियोजित 2,500 कर्मचारियों से आगे कोई छंटनी नहीं की जाएगी। एक सूत्र ने बताया कि कंपनी ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर केयर, इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस और अन्य क्षेत्रों में कुछ कार्यों को आउटसोर्स करने की योजना बना रही है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, प्रबंधन मौजूदा कर्मचारियों के जाने से पहले नए भागीदारों को लाना चाहता था। छंटनी अब हुई है। उन्होंने कहा, अभी कंपनी कर्मचारियों के साथ ज्यादातर संवाद व्हाट्सएप के माध्यम से कर रही है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि यह बात कम लीक हो... कंपनी ने नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद हमें सेवरेंस पैकेज का आश्वासन दिया है। टाइगर ग्लोबल समर्थित एडटेक यूनिकॉर्न की ताजा छंटनी ऐसे समय में हुई है, जब स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार फंडिंग की कमी से जूझ रहा है। अकेले जनवरी 2023 के पहले दो हफ्तों में कम से कम 1500 स्टार्टअप कार्यबल ने नौकरी खो दीहै। पिछले एक साल में 22,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की गई है। बायजू के एक पूर्व कर्मचारी ने कहा, इस बार वाइस प्रेसीडेंट और शीर्ष स्तर के प्रबंधक भी प्रभावित हुए हैं। जबकि हटाए गए कर्मचारियों में से अधिकांश या 95% जूनियर पदों पर हैं, ये सीनियर लेवल की भूमिकाओं का हिस्सा थे।

शेयर बाजार की पूंजी के लिहाज से भारत फिर पांचवें स्थान पर पहुंचा, जानें किस देश से था पिछड़ा?

एनटीवी न्यूज

नई दिल्ली. अदाणी समूह के शेयरों की बिकवाली के दौरान फ्रांस से कुछ समय के लिए पिछड़ने के बाद बाद भारत ने मूल्य के हिसाब से दुनिया के शीर्ष इक्विटी बाजारों में पांचवें स्थान पर फिर से कब्जा कर लिया है। ब्लूमबर्ग की ओर से संकलित आंकड़ों के अनुसार, भारत का बाजार पूंजीकरण शुक्रवार को 3.15 ट्रिलियन डॉलर था, जो फ्रांस से अधिक है। सूची में ब्रिटेन सातवें स्थान पर है। इस सूची में प्रत्येक देश में प्राथमिक लिस्टिंग वाली कंपनियों के संयुक्त मूल्य को दर्शाया जाता है।

आय वृद्धि के परिदृश्य से दक्षिण एशियाई देश के शेयरों में मजबूती आई है। जिन्होंने पिछले दो वर्षों से अधिकांश वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि भारत के बाजार का कुल मूल्य 24 जनवरी की तुलना में अब भी लगभग 6% कम रहा। अदाणी शेयरों में बिकवाली शुरू होने से एक दिन पहले बाजार वर्तमान की तुलना में अधिक मजबूत थे। हालांकि निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए समूह की ओर से उठाए गए कदमों से इसके शेयरों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन अदाणी समूह मार्केट कैप में पहले की तुलना में लगभग 120 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है।

नवंबर महीने के बाद भारतीय शेयर बाजारों से धन निकालने के बाद विदेशी निवेशक इस महीने के 9 फरवरी तक सात में से दो सत्रों के दौरान शुद्ध खरीदार रहे। यह खरीद फरवरी की शुरुआत में पूंजीगत खर्च बढ़ाने की सरकार की योजना के बाद की गई थी। जबकि केंद्रीय बैंक ने पिछले सप्ताह ब्याज दर में वृद्धि की धीमी गति का भी संकेत दिया है।

हफ्ते के पहले दिन बाजार में सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स 30 अंक चढ़ा, निफ्टी 17850 के पास

नई दिल्ली. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सपाट शुरुआत हुई है। शुरुआत में 40 अंकों की बढ़त के बाद बाजार में बिकवाली हावी होती दिखी। फिलहाल सेंसेक्स 149.50 अंकों की बढ़त के साथ 60,533.20 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 31.20 अंकों की बढ़त के साथ 17825.30 अंकों पर कारोबार कर रहा है। इस दौरान डेल्हीवरी शेड्स के शेयरों में 5% की गिरावट जबकि अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में 2 प्रतिशत की बढ़त दिख रही है। शुरुआती कारोबार में टाटा स्टील और पावरग्रिड जैसे शेयरों में दिखी उछाल बाजार में शुरुआताी कारोबार में आईटी सेक्टर के शेयरों में कमजोरी दिख रही है। इंफोसिस के शेयरों में दो प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर सोमवार के कारोबारी सेशन के दौरान मेटल सेक्टर के शेयरों में मजबूती है। अदाणी एंटरप्राइजेस के शेयरों में भी हल्की मजबूती दिख रही है। टाटा स्टील, टाइटन, पावरग्रिड और एलएंडटी के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।

शीर्ष-7 शहरों में मकानों का किराया 23% बढ़ा, सबसे ज्यादा नोएडा सेक्टर-150 में हुई वृद्धि

नई दिल्ली. संपत्ति सलाहकार एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक, 2019 से 2022 के बीच एक हजार वर्ग फुट वाले दो बीएचके फ्लैट के किराये सभी सात शहरों में बढ़े हैं। देश के शीर्ष सात शहरों में पिछले तीन सालों में मकानों के औसत मासिक किराये में 23 फीसदी की वृद्धि हुई है। संपत्ति सलाहकार एनारॉक के आंकड़ों के मुताबिक, 2019 से 2022 के बीच एक हजार वर्ग फुट वाले दो बीएचके फ्लैट के किराये सभी सात शहरों में बढ़े हैं। इसमें सबसे ज्यादा 23 फीसदी की बढ़त नोएडा सेक्टर 150 में हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, नोएडा सेक्टर 150 में 2019 में 1,000 वर्ग फुट के 2 बीएचके मकान का किराया 15,500 रुपये था। 2022 में यह बढ़कर 19,000 रुपये हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि ज्यादा कंपनियां अब कर्मचारियों को ऑफिस बुला रही हैं, इसलिए मकानों की मांग बढ़ रही है।

2 बीएचके का किराया

शहर	2019	2022
गुरुग्राम	25,000	28,500
द्वारका	19,500	22,000
मुंबई	45,000	51,000
कोलकाता	19,000	22,000
बंगलूरू	21,000	24,000
पुणे	17,500	21,000
चेन्नई	16,000	18,000

रिपोर्ट में कहा गया है कि मकानों का किराया इस साल भी बढ़ सकता है। कर्मचारी अब घर खरीदने के बजाय कुछ समय तक किराये पर ही रहने की सोच रहे हैं। हैदराबाद के हाईटेक शहर में तीन साल में किराया 7 फीसदी बढ़कर 24,700 रुपये मासिक हो गया है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फरवरी में निकाले 9,600 करोड़, महंगा है भारतीय बाजार

एफपीआई ने जनवरी में कुल 28,852 करोड़ रुपये की निकासी बाजार से की थी। पिछले सात महीने में किसी एक माह में यह सर्वाधिक निकासी थी। दिसंबर में इन्होंने 11,119 करोड़ और नवंबर में 36,238 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) ने चालू माह में 10 फरवरी तक शेयर बाजार से 9,600 करोड़ रुपये निकाले हैं। भारतीय बाजार का मूल्यांकन अन्य बाजारों की तुलना में महंगा है। इसलिए विदेशी निवेशक इन पैसों को दूसरे उभरते बाजारों में लगा रहे हैं। हालांकि, डेट बाजारों में इन्होंने 2,154 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने जनवरी में कुल 28,852 करोड़ रुपये की निकासी बाजार से की थी। पिछले सात महीने में किसी एक माह में यह सर्वाधिक निकासी थी। दिसंबर में इन्होंने 11,119 करोड़ और नवंबर में 36,238 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

विश्लेषकों का मानना है कि आगे चलकर विदेशी निवेशकों का रुझान उतार-चढ़ाव का रहेगा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्याज दरों में लगातार छठीं बार वृद्धि की है। जब तक अदाणी समूह के मुद्दों पर कोई स्पष्टता नहीं आती है, तब तक विदेशी निवेशकों का यह रुझान बना रहेगा।

28,852 करोड़ रुपये की जनवरी में हुई थी शेयर बाजार से निकासी

विदेशी निवेशकों ने वित्तीय सेवाओं के सेगमेंट से ज्यादा निकासी की है। हालांकि, ऑटो और कलपुर्जों वाले सेगमेंट में निवेश किया है। आईटी में जनवरी में इन निवेशकों ने बिकवाली की थी। लेकिन इस महीने इसमें खरीदारी किए हैं।

गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में विदेशी निवेश पर कर लगाने की तैयारी

आयकर विभाग अप्रवासी निवेशकों पर कर लगाने के मकसद से गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) का पता लगाने के लिए आयकर कानून के तहत संशोधित मूल्यांकन नियम जारी कर सकता है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस संशोधन की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है कि आयकर अधिनियम व फेमा कानून में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के एफएमवी की गणना के लिए अलग-अलग तरीके हैं। आयकर अधिनियम के नियम 11यूए को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को (फेमा) के अनुरूप बनाने के लिए हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए फिर निर्धारित किया जाएगा। 11यूए अचल संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति के एफएमवी के निर्धारण से जुड़ा है।

तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर की कीमतें

दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है।

नई दिल्ली. तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने दिल्ली और चेन्नई में तेल के दामों में बदलाव किया है। सरकार ने कुछ महीने पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी। आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।

जानें प्रमुख महानगरों में कितनी है कीमत

आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में एक लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार हैं।

शहर	डीजल	पेट्रोल
दिल्ली	89.62	96.72
मुंबई	94.27	106.31
कोलकाता	92.76	106.03
चेन्नई	94.24	102.63

(पेट्रोल-डीजल की कीमत रुपये प्रति लीटर में है।)

जानिए आपके शहर में कितना है दाम

पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा।

बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

उतार-चढ़ाव के बीच चुनें अच्छा निवेश, योजना के जरिये तीन से ज्यादा संपत्तियों में लगाएं पैसा

नई दिल्ली। मौजूदा दौर में हम ज्याद महंगाई, उच्च ब्याज दरों, कम तरलता, अस्थिरता और भू-राजनीतिक चिंताओं के चलते एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही, शेयर बाजारों में आगे भी भारी उतार-चढ़ाव रहने का अनुमान है। ऐसे में बेहतर फायदे के लिए आपको कई संपत्तियों में निवेश करना चाहिए। इससे आपके घाटे का जोखिम कम हो सकता है। इसका गणित बताती अजीत सिंह की रिपोर्ट... आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) एस नरेन का मानना है कि किसी निवेशक के लिए सभी परिसंपत्तियों के वर्गों में निवेश करने का सबसे आसान तरीका मल्टी-एसेट फंड है। इस एक फंड में एक ही कैटेगरी के माध्यम से तीन या अधिक संपत्तियों में आप निवेश कर सकते हैं। यह फंड इक्विटी में 10-80 फीसदी, डेट में 10-35%, गोल्ड में 10-35% और रीट एवं इनविट में 0-10% निवेश करता है। विभिन्न एसेट क्लास में निवेश की ऐसी रणनीति का उद्देश्य इक्विटी में निवेश करके पूंजी बढ़ाना, डेट में निवेश करके स्थिरता और अच्छा रिटर्न अर्जित करना है। सोने में निवेश करके महंगाई से बचाव करना है।

एनएवी में 48 गुना की बढ़त

फंड की इस स्कीम ने 5 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि में कभी भी नकारात्मक रिटर्न नहीं दिया है। स्थापना के बाद से इसका नेट असेट वैल्यू यानी एनएवी लगभग 48 गुना बढ़ गया है। जब पोर्टफोलियो निर्माण की बात आती है, तो इक्विटी के मामले में यह स्कीम लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेश कर सकती है। वृद्धि या वैल्यू स्टाइल के विपरीत इसके निवेश के तरीके अलग होते हैं। इसे अक्सर कैटेगरी के अन्य फंडों द्वारा अपनाया जाता है।

इक्विटी में ज्यादा निवेश का अवसर

इस फंड में इक्विटी में निवेश इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, जहां दिशात्मक कॉल के आधार पर हमें आर्थिक चक्र में रखा जाता है। इसके अलावा, स्कीम समग्र पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ाने और महंगाई को पीछे छोड़ने के उद्देश्य के लिए तेल, सोना, चांदी जैसी वस्तुओं के लिए रणनीतिक निवेश का फैसला ले सकती है। स्कीम वर्तमान में इक्विटी में ज्यादा निवेश कर रही है, क्योंकि आर्थिक रिकवरी चालू है।

डीआरआई चीफ ने कहा- बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी, हर महीने जब्त होती है 1,000 करोड़ की प्रतिबंधित वस्तुएं

राजस्व खुफिया महानिदेशालय के महानिदेशक मोहन कुमार सिंह ने फिक्की कास्केड के सम्मेलन में कहा कि आज तस्कर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार माल की तस्करी के लिए जटिल तरीकों व तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।

नई दिल्ली. तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। इस मुद्दे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डीआरआई हर महीने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबंधित सामग्री जब्त करता है। राजस्व खुफिया महानिदेशालय के महानिदेशक मोहन कुमार सिंह ने फिक्की कास्केड के सम्मेलन में कहा कि आज तस्कर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार माल की तस्करी के लिए जटिल तरीकों व तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। सिंह ने कहा, जालसाजी और तस्करी के मामले में इस तरह का अवैध व्यापार एक वैश्विक जोखिम है। इसका आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

वैश्विक जीडीपी को दो लाख करोड़ डॉलर की चपत

विश्व कस्टम संगठन (डब्ल्यूसीओ) के निदेशक पीके दास ने कहा कि हर साल तस्करी से दुनिया की अर्थव्यवस्था को दो लाख करोड़ डॉलर का नुकसान होता है। फिक्की कास्केड के अध्यक्ष अनिल राजपूत ने कहा, हमने सम्मेलन में जागरूकता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ने का संकल्प लिया और तस्करी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का संकल्प लिया।

पीएलआई... दूरसंचार क्षेत्र को राशि मिलनी शुरू

दूरसंचार विभाग ने 2021-22 के लिए अपना लक्ष्य पूरा करने वाले निर्माताओं को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) रकम देना शुरू कर दिया है। जीएक्स टेलीकॉम ने कहा कि उसे इस योजना के तहत दूरसंचार विभाग से रकम मिली है। कंपनी के पास 3.5 लाख यूनिट जीपीओएन उपकरण बनाने की क्षमता है, जिनका उपयोग ब्रॉडबैंड नेटवर्क शुरू करने के लिए किया जाता है। वैश्विक बाजार में भारत में बने टेलीकॉम उपकरणों की मांग बढ़ी है। दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने कहा, प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली योजना के तहत जीएक्स इंडिया पहली कंपनी है।

ऑयल इंडिया को 1,746 करोड़ का लाभ

सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया को दिसंबर तिमाही में 1,746 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले यह 1,245 करोड़ रुपये था। यह इसके इतिहास में अब तक का सर्वोच्च लाभ है। कंपनी ने प्रति शेयर दस रुपये लाभांश देने की घोषणा की है। कंपनी ने रविवार को कहा कि तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ने से उसके फायदे पर असर दिखा है।

टाटा स्टील की 7 कंपनियों का विलय 2024 तक होगा पूरा

टाटा स्टील की सात कंपनियों का विलय 2023-24 में पूरा होने की उम्मीद है। इन कंपनियों में टाटा स्टील लांग प्रोडक्ट, द टिनप्लेट कंपनी, टाटा मेटालिक्स, टीआरएफ, इंडियन स्टील एवं वायर प्रोडक्ट और टाटा स्टील माइनिंग एवं एसएंडटी माइनिंग कंपनी आदि हैं। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टीवी नागेंद्रन ने रविवार को बताया कि सितंबर, 2022 में बोर्ड ने 7 कंपनियों के विलय को मंजूरी दी थी। इससे लागत घटाने में मदद मिलेगी। हालांकि, विलय को पूरा करने में नियामकीय प्रक्रियाओं की भी भूमिका होगी और इस वजह से यह अगले वित्त वर्ष में पूरा हो सकता है।

PM मोदी ने लड़ाकू विमानों की जानकारी ली, पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों से मिले राजनाथ

एनटीवी न्यूज

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में एयरो इंडिया मेगा शो का वायुसेना अड्डे येलहंका पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। यहां पीएम ने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया और कहा कि एयरो इंडिया सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि यह भारत की ताकत है। इससे पहले वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने उद्घाटन समारोह में गुरुकुल फॉर्मेशन का नेतृत्व किया और फाइटर जेट से उड़ान भरी। एयरो इंडिया शो के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें...

नेपाल-बांग्लादेश-श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल से मिले राजनाथ सिंह

एयरो इंडिया शो से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी, नेपाल के रक्षा मंत्री हरी प्रसाद उप्रेती और श्रीलंका के रक्षा राज्य मंत्री प्रेमिता बंडारा से मुलाकात की।

बेंगलुरु: नेपाल के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया शो में हिस्सा लेने आए नेपाल के रक्षा मंत्री हरी प्रसाद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-नेपाल के रिश्तों को और मजबूत करने के साथ रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की बात कही।

येलहंका में एयर शो जारी

कर्नाटक: बेंगलुरू में येलहंका के वायु सेना स्टेशन में एयरो इंडिया 2023 के 14वां संस्करण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अन्य उपस्थित हैं।

'अमृतकाल का भारत फाइटर पायलट की तरह'

पीएम मोदी ने कहा, ₹अमृतकाल' का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसको ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता। जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। एक बात और, भारत की रफ़्तार चाहे जितनी तेज हो लेकिन वो हमेशा जमीन से भी जुड़ा रहता है।₹

'21वीं सदी का नया भारत कोई मौका नहीं खोएगा'

₹आज भारत की संभावनाओं और सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही हैं। आकाश में गर्जना करते तेजस विमान 'मेक इन इंडिया' की सफलता का प्रमाण है। 21वीं सदी का नया भारत अब ना कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कसर छोड़ेगा। हम कमर कस चुके हैं। भारत ने बीते 8-9 साल में अपने यहां डिफेंस के क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। हम अभी इसे केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष 2024 -25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 5 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। भारत अब डिफेंस उत्पादक देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा।₹

पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई देश नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के साथ ढलने लगती हैं। आज का ये आयोजन भारत की नई सोच को भी प्रतिबिंबित करता है। आज ये आयोजन केवल एक शो नहीं है, ये भारत की स्ट्रेंथ भी है और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है।

एयरो इंडिया शो कर्नाटक के लिए बेहद खास

एयरो इंडिया के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन एक वजह से बहुत खास है। यह कर्नाटक जैसे एक ऐसे राज्य में हो रहा है जिसे तकनीक की दुनिया में विशेष महारत हासिल है। इस आयोजन से एयरो स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। कर्नाटक के युवाओं के लिए नई संभावनाएं पैदा होंगी।

रक्षा मंत्री ने एयरो इंडिया की सफलता का जिक्र करते हुए कहा, ₹इस तरह की विशाल भागीदारी, भारत की उभरती व्यापारिक क्षमता में घरेलू एवं वैश्विक व्यापारी समुदाय के एक नए विश्वास का प्रमाण है। मैं आप सभी से रक्षा उत्पादन हब बनने की ओर भारत की यात्रा में सहयात्री बनने का आह्वान करता हूं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य-पराक्रम और विज्ञान की भूमि रही है। यह प्रदेश औद्योगिकरण में पायनियर रहा है और हमारे देश के आर्थिक विकास में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एयरो इंडिया के आयोजन के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थान है।

वीआर चौधरी ने किया फॉर्मेशन का नेतृत्व

वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने एयरो इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह में गुरुकुल फॉर्मेशन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में एयरो इंडिया मेगा शो का वायुसेना अड्डे येलहंका पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी उद्घाटन समारोह में गुरुकुल फॉर्मेशन का नेतृत्व करेंगे और फाइटर जेट से उड़ान भरेंगे।

'केंद्र के दबाव में दिया गया अयोध्या विवाद पर फैसला', SC के पूर्व जज को राज्यपाल बनाए जाने पर बोले अल्वी

एनटीवी न्यूज

राशिद अल्वी ने भाजपा सरकार पर धर्म के आधार पर देश को बांटने का भी आरोप लगाया और कहा कि जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाए जाने से लोगों की न्यायपालिका में आस्था घटी है।

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के दबाव में दिया गया। राशिद अल्वी ने यह आरोप पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने के बाद लगाया है। बता दें कि जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला दिया था।

राशिद अल्वी बोले- न्यायपालिका में घटी लोगों की आस्था

कांग्रेस नेता ने कहा कि 'लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि फैसला केंद्र सरकार के दबाव में दिया गया। न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 50 में इसका जिक्र है'। राशिद अल्वी ने भाजपा सरकार पर धर्म के आधार पर देश को बांटने का भी आरोप लगाया और कहा कि जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाए जाने से लोगों की न्यायपालिका में आस्था घटी है।

जस्टिस एस अब्दुल नजीर चार जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट जज के पद से रिटायर हुए। जस्टिस नजीर कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे, जिनमें तीन तलाक, अयोध्या-बाबरी विवाद, नोटबंदी मामला और निजता का अधिकार जैसे मामले शामिल हैं।

बोले- न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि जजों को सरकारी पदों पर नियुक्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार ने करीब 50 फीसदी रिटायर्ड जजों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया है, इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कम हुआ है। उल्लेखनीय है कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को भी केंद्र सरकार ने राज्यसभा का सदस्य बनाया है। रिटायर्ड जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला दिया था। इस पर राशिद अल्वी ने कहा कि सरकार को न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। न्यायपालिका का कार्यपालिका से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए और सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए।

इनसाइड

समलैंगिक जोड़े की याचिका पर होगी सुनवाई, केरल हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने समलैंगिक जोड़े को मनोचिकित्सक के साथ परामर्श सत्र में भाग लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद समलैंगिक जोड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट एक समलैंगिक जोड़े की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने समलैंगिक जोड़े को मनोचिकित्सक के साथ परामर्श सत्र में भाग लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद समलैंगिक जोड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को ही इस मामले की सुनवाई करेगी। विक्टोरिया गौर की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर भी कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट वकील एल विक्टोरिया गौरी की मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन की याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी। कोर्ट मामले में सात फरवरी को सुनवाई करेगी।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ के समक्ष केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला वकील को पदोन्नत करने का प्रस्ताव कथित तौर पर तब विवादास्पद हो गया, जब उनके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से कथित संबद्धता के बारे में खबरें सामने आईं। न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित वकील के मुस्लिम और ईसाइयों के बारे में कुछ बयान सामने आए हैं।

धर्मांतरण: राज्य कानूनों से संबंधित याचिकाओं पर 17 मार्च को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह जबरन धर्मांतरण के दो अलग-अलग मुद्दों और अंतर्धार्मिक विवाहों के कारण होने वाले धर्मांतरण पर राज्य के विभिन्न कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 17 मार्च को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से वकील अश्विनी उपाध्याय ने आग्रह किया था कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ उनकी याचिका उन याचिकाओं के बैच से अलग थी, जो धार्म परिवर्तन पर विभिन्न राज्य कानूनों की वैधता को चुनौती दे रही हैं। उन्होंने बेंच से कहा कि मैं न तो राज्य के कानूनों का समर्थन कर रहा हूं और न ही उनका विरोध कर रहा हूं। मेरी याचिका जबरन धर्मांतरण के अलग-अलग मुद्दे से संबंधित है। उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका पर अलग से सुनवाई की मांग की।

मेले में गैस सिलेंडर फटा, चार लोगों की मौत, पांच घायल

कोलकाता. पुलिस ने बताया कि गुब्बारा विक्रेता द्वारा गुब्बारे को भरने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। तभी यह हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक गांव के मेले के दौरान गैस सिलेंडर में भीषण ब्लास्ट हुआ। इसकी चपेट में आकर चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, घटना जॉयनगर थाना क्षेत्र के बंतरा गांव में रविवार रात करीब 10 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि गुब्बारा विक्रेता द्वारा गुब्बारे को भरने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। तभी यह हादसा हुआ। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान साहिन मोल्ला (13), कुतुबुद्दीन मिस्त्री (35), अबीर गाजी (8) और गुब्बारा विक्रेता मुचिराम मंडल (35) के रूप में हुई है। सभी घायलों को बारुईपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सीएम साहा ने किया 36 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, कहा- पीएम मोदी ने बदली पूरी राजनीति

एनटीवी संवाददाता

माणिक साहा ने कहा, कांग्रेस और वाम दल पारंपरिक राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी राजनीति ही बदल दी है। किन लोगों के साथ रहने से कितने मतदान मिलेंगे यह लोग उसी में लगे हैं, लेकिन भाजपा सबके लिए काम करती है।

त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दल 36 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने वाले हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान साहा ने कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा 2018 की तुलना में और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। सीटों पर जीत हासिल करेगी, वहीं हमारे सहयोगी दल आठ सीटों पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा, इस तरह हम 36 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने वाले हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने बदली पूरी राजनीति

माणिक साहा ने कहा, कांग्रेस और वाम दल पारंपरिक राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी राजनीति ही बदल दी है। किन लोगों के साथ रहने से कितने मतदान मिलेंगे यह लोग उसी में लगे हैं, लेकिन भाजपा सबके लिए काम करती है। उन्होंने ग्रेटर टिपरालैंड को लेकर कहा, मैंने बार-बार कहा कि ग्रेटर टिपरालैंड की सीमा कहां है? वे कभी बोलते हैं कि यह बांग्लादेश में है, कभी बोलते हैं कि असम, मिज़ोरम में कुछ हिस्सा है। अगर हम इसपर बात करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि यह भाषाई और सांस्कृतिक पर है। वे ठीक से इसको परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं।

राज्य व केंद्र में एक ही सरकार होने से फायदा

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, केंद्र व राज्य में अगर एक ही पार्टी की सरकार होती है तो कुछ भी चीज मांगने में आसानी हो जाती है। मैंने पहले भी देखा था कि केंद्रीय मंत्रियों से मिलने में बहुत मुश्किल होती थी। अगर एक ही सरकार होगी तो समय भी तुरंत मिल जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं था और जनता इसको समझती भी है। उन्होंने आगे कहा, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से हटाना भारत के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ है। इस वजह से भी त्रिपुरा जरूरी है। इतने लोगों को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा और ऐसा फिर से न हो इसलिए हमारे पार्टी के नेता भी चिंतित रहते हैं।

'अमृतकाल का भारत फाइटर पायलट की तरह, अवसर नहीं छोड़ेगा', पढ़ें PM मोदी के भाषण की पांच बड़ी बातें

एनटीवी संवाददाता

पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई देश नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के साथ ढलने लगती हैं। आज का ये आयोजन भारत की नई सोच को भी प्रतिबिंबित करता है।

बेंगलुरु. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एयरो इंडिया शो में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। इससे पहले अपने संबोधन में पीएम ने भारत की बढ़ती रक्षा ताकत और मेक इन इंडिया की उपलब्धियों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, ₹अमृतकाल' का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसको ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता। जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है।

पीएम मोदी के भाषण की पांच अहम पॉइंट्स...

आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। एक बात और, भारत की रफ़्तार चाहे जितनी तेज हो लेकिन वो हमेशा जमीन से भी जुड़ा रहता है।

आज भारत की संभावनाओं और सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही हैं। आकाश में गर्जना करते तेजस विमान 'मेक इन इंडिया' की सफलता का प्रमाण है। 21वीं सदी का नया भारत अब ना कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कसर छोड़ेगा। हम कमर कस चुके हैं।

भारत ने बीते 8-9 साल में अपने यहां डिफेंस के क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। हम अभी इसे केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष 2024 -25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 5 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। भारत अब डिफेंस उत्पादक देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई देश नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के साथ ढलने लगती हैं। आज का ये आयोजन भारत की नई सोच को भी प्रतिबिंबित करता है। आज ये आयोजन केवल एक शो नहीं है, ये भारत की स्ट्रेंथ भी है और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है।

एयरो इंडिया के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन एक वजह से बहुत खास है। यह कर्नाटक जैसे एक ऐसे राज्य में हो रहा है जिसे तकनीक की दुनिया में विशेष महारत हासिल है। इस आयोजन से एयरो स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। कर्नाटक के युवाओं के लिए नई संभावनाएं पैदा होंगी।

अदाणी मुद्दे पर हंगामे के बीच राज्यसभा 13 मार्च तक स्थगित, लोकसभा में कार्यवाही जारी

संसद के बजट सत्र में सोमवार की शरुआत हंगामे के बीच हुई। राज्यसभा में अदाणी मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। इस बीच एलओपी मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के कुछ अंश रिकॉर्ड से निकाले जाने को लेकर भी विपक्षी सांसद भड़क गए और सभापति के आसन के पास पहुंच गए। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 13 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, हम अदाणी मामले में चर्चा चाहते हैं, लेकिन केंद्र ऐसा नहीं चाहता है। हमें इस मुद्दे को सामने रखने का एक भी मौका नहीं मिला। जेपीसी जांच के आदेश क्यों नहीं दिए गए? पीएम जिस तरह से संसद में बोलते हैं, उस तरह से पीएम को बोलना नहीं चाहिए। राज्य सभा में हंगामे के दौरान सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह, इमरान प्रतापगढ़ी, शक्ति सिंह गोहिल, संदीप पाठक और कुमार केतकर सहित अन्य वेल में पहुंच गए। इसके बाद सभापति ने सभी सांसदों को चेतावनी जारी की। संसद में विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 11:30 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के अंश निकाले जाने के बाद से हंगामा कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय के नोटिस पर कहा, राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी कहा था वह पहले से पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग बोलते-लिखते हैं वही बात उन्होंने कही है। इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। इसलिए वह उसी हिसाब से नोटिस का जवाब देंगे। माकपा सांसद डॉ. जॉन ब्रिट्स ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्काल लागू करने का अनुरोध किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, बिना स्पीकर को नोटिस दिए आप प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। हमने राहुल गांधी को 15 फरवरी तक स्पीकर को सबूत दिखाने के लिए कहा है जो उनके दावों को साबित कर सकता है या उन्हें संसद में माफी मांगनी चाहिए अन्यथा वह अपनी लोकसभा सीट खो देंगे। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों को शांत करवाते हुए सभापति ने कहा, सभी सांसद अपने आचरण में संविधान निर्माताओं की भावना को रखें और सदन की कार्यवाही में किसी तरह का व्यवधान न आने दें।